सोशल मीडिया से जुड़ें
NewsTransportVishesh
YouTube
Digital Edition

न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

वर्ष 1, अंक 113, नई दिल्ली, रविवार, 19 फरवरी 2023, पेज 8

NEWS NTV TRANSPORT VISHESH
www.newstransportvishesh.com
सबसे तेज, सबसे पहले
आपको पहुंचाये
परिवहन क्षेत्र की सभी जानकारियां
09212122095
09811732095

03 राजधानी में ड्रोन से होगा मच्छरों पर वार
05 ऑटो इंडस्ट्री के लिए कैसा रहा ये सप्ताह?
08 नीतीश के इस दावे में कितना दम, समझिए समीकरण

आज का सुविचार

सफलता की लड़ाई अकेली ही लड़नी पड़ती है, सैलाब उमड़ता है जीत जाने के बाद।

इनसाइड

19 फरवरी को येलो लाइन पर मेट्रो की सेवाएं रहेंगी बाधित

नई दिल्ली। कश्मीरी गेट और विश्वविद्यालय स्टेशनों के बीच दिल्ली मेट्रो का परिचालन मेंटेनेंस के काम के चलते रविवार को कुछ घंटों के लिए आंशिक रूप से बाधित रहेगा। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने एक बयान में कहा कि 19 फरवरी को येलो लाइन (यानी हुडा सिटी सेंटर से समयपुर बादली) के कश्मीरी गेट और विश्वविद्यालय खंड के बीच निर्धारित ट्रैक मेंटेनेंस कार्य करने के लिए, इस खंड में आने वाले दो स्टेशनों यानी सिविल लाइंस और विधानसभा स्टेशन पर सुबह 6.30 बजे तक मेट्रो सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। सिविल लाइंस और विधानसभा मेट्रो स्टेशन राजस्व सेवाओं की शुरुआत से सुबह 6.30 बजे तक बंद रहेंगे। इस अवधि के दौरान कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन और विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशनों के बीच मुफ्त फीडर बस सेवा के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।

जल्द आएंगी फ्लेक्स इंजन कारें, नितिन गडकरी ने कहा- खोज रहे कचरे से सड़क बनाने के तरीके

इकॉनोमिक टाइम्स की ग्लोबल बिजनस समिट के दूसरे दिन रोड एंड हाइवे मंत्री नितिन गडकरी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। समिट में उन्होंने कहा कि साल 2025 तक 2 लाख किलोमीटर का नेशनल हाईवे तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि भारत की सड़कों को अमेरिका जैसी बनाने की दिशा में काम जारी है।

एनटीवी संवाददाता

नई दिल्ली : भारत की सड़कों को अमेरिका जैसी बनाने की दिशा में काम जारी है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने फिर से अपनी बात को दोहराया है। वे इकॉनोमिक टाइम्स की ग्लोबल बिजनस समिट 2023 (Global Business Summit) में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि एनएचएआई (NHAI) ने 16,000 किलोमीटर रोड कॉन्ट्रैक्ट देने का लक्ष्य रखा है। गडकरी ने कहा कि एनएचएआई बांड्स पर 8.50 फीसदी का ब्याज ऑफर हो रहा है। इसमें लोगों को निवेश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आठ लाख करोड़ रुपये के सागरमाला प्रोजेक्ट को पहले ही जारी किया जा चुका है। गडकरी ने समिट में कहा कि साल 2025 तक 2 लाख किलोमीटर के नेशनल हाइवेज का लक्ष्य है।

हर दिन बन रहा 38 किलोमीटर हाईवे

गडकरी ने कहा कि हर दिन 38 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। गडकरी ने उनके मंत्रालय के तहत 6 कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड रेकॉर्ड के बारे में भी बताया। गडकरी ने कहा, 'दिल्ली से हरिद्वार, देहरादून, अमृतसर और श्रीनगर के बीच यात्रा का समय कम किया जाएगा।' उन्होंने कहा कि पेट्रोल और एथेनॉल से चलने वाली फ्लेक्स इंजन कारें जल्द ही आएंगी। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट चिंता की बात है। 124 जिलों में एग्रो-इनिशिएटिव्ज पर फोकस किया जाएगा।

कचरे से बनेगी सड़क

गडकरी ने बताया कि धौलाकुआं (दिल्ली) से मानेसर (हरियाणा) रोपवे मास ट्रांजिट सिस्टम पर विचार किया जा रहा है। जोजिला टनल (जम्मू-कश्मीर) को अगले साल जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में नगर निगम के ठोस कचरे का उपयोग करने के तरीके तलाशे जा रहे हैं। गडकरी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पूंजी की कोई कमी नहीं है। गडकरी ने 'गोबर से डिस्टेंपर पेंट' पहल की बात की है।

दिल्ली से जयपुर जाने में लगेंगे 2 घंटे

गडकरी ने बताया कि 8 लेन का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे होगा। इसमें 276 किमी काम पूरा कर दिया गया है। अब दिल्ली से जयपुर जाने में 2 घंटे लगेंगें। वहीं, दिल्ली से मुंबई जाने में 12 घंटे लगेंगे। इसकी लंबाई 1386 किलोमीटर है। यह एशिया में सबसे लंबा है। यह एक्सप्रेस-वे कई सारे फायदे देगा।

मेट्रो की रेड लाइन पर लगी पहली स्वदेशी तकनीक, मेट्रो ट्रेनें खुद होंगी कंट्रोल

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर पहली स्वदेशी सिग्नलिंग प्रणाली आई-एटीएस का शुभारंभ किया गया है. इससे ट्रेनें ऑटोमैटिक रूप से संचालित होंगी. प्लेटफॉर्म पर जल्दी-जल्दी आने वाली ट्रेनों की सुविधा के लिए यह तकनीक काफी उपयोगी है.

भारत सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत दिल्ली मेट्रो ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर स्वदेश विकसित भारत की पहली सिग्नलिंग प्रणाली (आई-एटीएस) का शुभारंभ किया गया है. यह कम्प्यूटर आधारित ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम है जो ट्रेनों को खुद ही कंट्रोल करेगा. रेल आधारित MRTS के क्षेत्र में दिल्ली मेट्रो का पहला ट्रेन कंट्रोल एवं सुपरविजन सिस्टम, आई-एटीएस (स्वदेशी-ऑटोमैटिक ट्रेन सुपरविजन) रेड लाइन (रिठाला से शहीद स्थल) पर परिचालन के लिए शुरू किया गया है. इसका उद्घाटन परिचालन नियंत्रण केंद्र (ओसीसी), शास्त्री पार्क में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव मनोज जोशी और दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने किया.

खास बात है कि इस स्वदेशी सिग्नलिंग प्रणाली को डीएमआरसी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) ने मिलकर बनाया है. इस उपलब्धि के साथ, भारत ने कुछ देशों की विशिष्ट सूची में छठे देश के रूप में अपना नाम दर्ज करवाया है जिनका अपना एटीएस सिस्टम है.

रेड लाइन के बाद अन्य लाइनों पर लगेगी तकनीक

बता दें कि रेड लाइन के बाद इस आई-एटीएस प्रणाली को दिल्ली मेट्रो के अन्य कॉरीडोर के अलावा फेज-4 परियोजना के अलग कॉरीडोर में भी प्रयोग किया जाएगा. आई-एटीएस की मदद से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मॉड्यूल को फेज-4 परियोजना के कॉरीडोर में लागू किया जाएगा. इसके अलावा, इस आई-एटीएस को रेल आधारित अन्य प्रणालियों के साथ-साथ भारतीय रेल के परिचालन में उपयोग किया जा सकता है।

दिल्ली में अब कॉन्ट्रैक्ट वाले बस ड्राइवरों को हर महीने लेनी होगी ट्रेनिंग, DTC ने जारी किया आदेश, न लेने पर होगी कार्रवाई

डीटीसी ने कॉन्ट्रेक्ट पर काम करने वाले सभी बस ड्राइवरों को अब हर महीने में 2 दिन की रिफ्रेशर ट्रेनिंग लेना जरुरी होगा। ड्राइवरों को मौखिक टेस्ट के साथ सेफ ड्राइविंग टिप्स भी सिखाई जाएगी। इसके लिए अलग-अलग माध्यमों से ट्रेनिंग दी जा रही है।

नई दिल्ली: सड़क हादसों को रोकने के लिए डीटीसी ने कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले सभी बस ड्राइवरों के लिए अब हर महीने में 2 दिन की रिफ्रेशर ट्रेनिंग लेना जरूरी कर दिया है। सभी डिपो मैनेजरों और रीजनल मैनेजरों से कहा गया है कि वे अपने डिपो में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले सभी ड्राइवरों के ग्रुप बनाकर उन्हें हर महीने दो दिन का रिफ्रेशर कोर्स करने के लिए नंद नगरी ट्रेनिंग डिपो भेजें और इसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करें। जो ड्राइवर हर महीने ट्रेनिंग नहीं लेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, अभी रेगुलर ड्राइवरों के लिए हर महीने ट्रेनिंग अनिवार्य नहीं की गई है, लेकिन उनकी भी रेगुलर काउंसिल की जाएगी और अलग-अलग तरीकों से उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा।

मौखिक टेस्ट के साथ दिए जा रहे सेफ ड्राइविंग के टिप्स

डीटीसी के सूत्रों के मुताबिक, इस बारे में एक औपचारिक आदेश दिसंबर में ही जारी कर दिया गया था और जनवरी से ट्रेनिंग शुरू भी हो गई है। सेफ ड्राइविंग के लिए ड्राइवरों को अलग-अलग माध्यमों से ट्रेनिंग दी जा रही है और उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने पर विशेष फोकस किया जा रहा है। विजुअल माध्यमों से भी ड्राइवरों को सेफ ड्राइविंग के टिप्स दिए जा रहे हैं। साथ ही उनके मौखिक टेस्ट भी लिए जा रहे हैं।

ओवर स्पीडिंग पर मेन फोकस

ट्रेनिंग में मुख्य रूप से इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि ड्राइवर ओवर स्पीडिंग न करें। रेडलाइट जंप न करें। जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस न करें। अपनी लेन में बसें चलाएं। स्टॉप पर प्रॉपर तरीके से बसें रोकें। दरवाजे खोलकर बस न चलाएं। फ्लाईओवर पर चढ़ते और उतरते समय स्पीड पर नियंत्रण रखें और ज्यादा अलर्ट रहें। ड्रंकन ड्राइविंग न करें, दूसरी गाड़ियों से पर्याप्त दूरी बनाकर रखें। बस चलाते वक्त फोन पर बात न करें। स्कूल, अस्पताल, मार्केट जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों से गुजरते वक्त सावधानीपूर्वक बस चलाएं।

हो रहे थे ज्यादा एक्सिडेंट

डीटीसी के सूत्रों का कहना है कि 2021 और 2022 में डीटीसी बसों से हुए सड़क हादसों के विश्लेषण में यह बात सामने आई कि रेगुलर ड्राइवरों के मुकाबले कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले बस ड्राइवरों से एक्सिडेंट ज्यादा हो रहे थे। इसी को देखते हुए अभी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले ड्राइवरों की रेगुलर ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। डीटीसी में 10,624 ड्राइवर तैनात हैं, जिनमें से 5,131 रेगुलर और 5,493 कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले ड्राइवर हैं। पिछले साल डीटीसी बसों से 28 जानलेवा सड़क हादसे हुए, जिनमें से 20 मामलों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले ड्राइवर बस चला रहे थे, जबकि सिर्फ 8 मामलों में रेगुलर ड्राइवर शामिल थे। इसी तरह 77 अन्य एक्सिडेंट्स में से 54 मामलों में कॉन्ट्रैक्चुअल और 23 मामलों में रेगुलर ड्राइवर शामिल थे।

शिमला से दिल्ली के लिए 2 बसें शुरू: रोहड़ू और रामपुर से बहाल की गई वॉल्वो सर्विस

एनटीवी संवाददाता

नई दिल्ली। राजधानी शिमला से दिल्ली रूट के लिए 2 और बसें शुरू कर दी गई हैं। बर्फबारी के बाद से बंद चल रहे रूटों को फिर से बहाल किया गया है। रोहड़ू और रामपुर से इन बसों की आवाजाही शुरू की गई है।

ऐसे में अब रामपुर व रोहड़ू से दिल्ली जाने वाले यात्री बस सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। निगम प्रबंधन की ओर से जनवरी माह में बर्फबारी की संभावना के चलते इन दोनों रूटों पर वॉल्वो बस सेवा बंद कर दी गई थी।

यह रहेगी बसों की टाइमिंग

रोहड़ू से दिल्ली के लिए वॉल्वो बस शाम 5 बजे चलेगी, जो रात 10 बजे शिमला पहुंचेगी। बस सेवा सुबह 6 बजे दिल्ली पहुंचेगी। इसके आगे दिल्ली के हिमाचल भवन पहुंचने का समय सुबह 6.30 बजे होगा। दिल्ली से रोहड़ू के लिए यह बस सेवा दिल्ली से शाम 9 बजे चलेगी और सुबह 6 बजे शिमला और 10 बजे रोहड़ू पहुंच जाएगी।

रामपुर से भी नाइट सर्विस चलेगी

रामपुर से दिल्ली के लिए वॉल्वो बस सेवा शाम 5 बजे चलेगी और रात 10.30 बजे बस शिमला पहुंचेगी। वहीं सुबह 6 बजे दिल्ली पहुंचने की समय रहेगा। दिल्ली से रामपुर के लिए यह बस सेवा शाम को 7.30 बजे चलेगी। सुबह 5 बजे यह शिमला पहुंचेगी। रामपुर पहुंचने का समय सुबह 10 बजे का होगा।

बर्फबारी में बंद रहती वॉल्वो सर्विस

ऊपरी शिमला में बर्फबारी के चलते बस रूटों को बंद कर दिया जाता है। HRTC के DDM पवन शर्मा ने बताया कि यह बस सेवाएं शुरू हो गई है। रामपुर व रोहड़ू से जाने वाले यात्री और शिमला से दिल्ली के लिए नाइट में जाने वाले यात्री इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

पिथौरागढ़ जा रहे श्रद्धालुओं की बस पलटी, हादसे में दस लोग घायल, दो महिलाओं को आई अधिक चोट

एनटीवी संवाददाता

बागेश्वर। दिल्ली के सैलानियों का दल शुक्रवार को बागेश्वर के एक होटल में ठहरा था। शनिवार सुबह श्रद्धालुओं का दल मिनी बस संख्या यूपी14 ईटी 1383 से बागेश्वर से पाताल भुवनेश्वर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में दूसरे वाहन को बचाने के चक्कर में बस पलट गई। बागेश्वर से पिथौरागढ़ के पाताल भुवनेश्वर गुफा के दर्शनों को जा रहे श्रद्धालुओं की बस कलना बैंड के पास सड़क पर पलट गई। हादसे में दस लोग घायल हो गए। दो महिलाओं को अधिक चोट है। यात्रियों में अधिकांश दिल्ली के रहने वाले हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली के सैलानियों का दल शुक्रवार को बागेश्वर के एक होटल में ठहरा था। शनिवार सुबह श्रद्धालुओं का दल मिनी बस संख्या यूपी14 ईटी 1383 से बागेश्वर से पाताल भुवनेश्वर के लिए रवाना हुआ। बस सुबह करीब 11 बजे जिला मुख्यालय से करीब नौ किमी. आगे कलना बैंड के पास पहुंची थी कि एक अन्य वाहन को बचाने के प्रयास में बस सड़क पर पलट गई।

बस में सवार निकिता शर्मा (31) पत्नी विकास निवासी दिल्ली, आकांक्षा (32) पति रोशन निवासी नई दिल्ली, आरके नागपाल (65) पुत्र आरएल नागपाल निवासी नई दिल्ली, राघव (24) पुत्र राजीव मल्होत्रा निवासी नई दिल्ली, अनाइशा (6) पुत्री रोशन निवासी नई दिल्ली, ललित (23) पुत्र सुरेंद्र निवासी नई दिल्ली, शीला (43) पत्नी अशोक कुमार निवासी नई दिल्ली, कुशुम (56) पत्नी सुरेंद्र निवासी नऊ दिल्ली, राजेश (29) निवासी उड़ीसा और पान सिंह (59) पुत्र धन सिंह निवासी कांडा बागेश्वर घायल हो गए।

टैंपल'स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण रजिस्टर्ड

कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063, कॉरपोरेट

कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

यह न केवल सरकार के लिए, बल्कि दिल्ली के सभी नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है : गहलोत

राजधानी दिल्ली में 'पिंक पास' की पावर 100 करोड़ महिलाओं ने बसों में की मुफ्त यात्रा

एनटीवी संवाददाता

दिल्ली में पिंक पास के चलते बस में महिला यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। दिल्ली सरकार की ओर से पेश की गई जानकारी के अनुसार, अब तक 100 करोड़ से अधिक महिलाओं को पिंक पास जारी किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने भी इस मौके पर कहा कि सभी नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है।

नई दिल्ली: 'पिंक पास' की पावर ने दिल्ली में हर तबके की महिलाओं का जीवन काफी आसान बना दिया है। इस पास के जरिए डीटीसी और क्लस्टर स्कीम की बसों में मुफ्त में यात्रा करके महिलाएं अब सुरक्षित तरीके से किसी भी वक्त आसानी से कहीं भी आ-जा सकती है। अब उन्हें आवागमन के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं रह गई है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अक्टूबर 2019 में दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई इस 'पिंक पास' योजना को महिलाओं का जबर्दस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को आंकड़े जारी करके बताया कि अब तक 100 करोड़ से अधिक महिलाओं को पिंक पास जारी किए जा चुके हैं और यह पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में दिल्ली सरकार द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है।

बस में महिला यात्रियों की संख्या में हुआ इजाफा

दिल्ली सरकार के मुताबिक, अक्टूबर 2019 में 'पिंक पास' योजना की शुरुआत से लेकर जनवरी 2023 के अंत तक 100 करोड़ से अधिक महिलाओं को बसों में यात्रा के लिए 'पिंक पास' जारी किए जा चुके हैं, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इस दौरान पिंक टिकट का इस्तेमाल करने वाली महिला यात्रियों की तादाद में भी काफी इजाफा भी हुआ है। बसों में महिला यात्रियों की संख्या 2020-21 में 25% और 2021-22 में 28% थी, जो 2022-23 में बढ़कर अब तक लगभग 33% हो गई है। दिल्ली सरकार पिंक पास पर अब तक कुल 1,000 करोड़ रुपये भी खर्च कर चुकी है।

इस अवसर पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि यह न केवल सरकार के लिए, बल्कि दिल्ली के सभी नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने यह दिखाया है कि कैसे मुफ्त यात्रा शहर में महिलाओं को सशक्त बना सकती है। पिछले कुछ सालों में महिला बस यात्रियों की बढ़ती संख्या इस योजना की सफलता को दर्शाती है। इस योजना से दिल्ली में रोजाना सफर करने वाली महिलाओं को काफी लाभ मिला है। दिल्ली भारत का पहला राज्य है, जहां इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना चल रही है।

बसों की राइडरशिप भी 75 प्रतिशत तक पहुंची

परिवहन मंत्री ने बताया कि दिल्ली में पिछले कुछ सालों में बस यात्रियों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले साल डीटीसी और डिम्ट्स की बसों में औसतन 36 लाख यात्रियों ने रोजाना सफर किया था। अगले कुछ महीनों में यात्रियों की संख्या बढ़कर प्रतिदिन 40 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। कोविड की वजह से बस यात्रियों की संख्या में जो कमी आई थी, वो भी अब धीरे-धीरे दूर होती जा रही है। 2019-20 में बस यात्रियों की संख्या 160 करोड़ से अधिक थी। जो 2020-21 में कोविड के कारण घटकर 71 करोड़ और 2021-22 में 93 करोड़ रह गई थी। अप्रैल 2022 से यह संख्या लगातार बढ़ रही है और अब यात्रियों की संख्या लगभग 125 करोड़ तक पहुंच गई है। यह प्री-कोविड टाइम में यात्रियों की संख्या का लगभग 75% है।

इनसाइड

मीनोपॉज के लक्षणों को कम करने के लिए महिलाएं जरूर करें इन 3 मुद्राओं का अभ्यास

ज्यादातर महिलाओं को 40 से 50 की उम्र में मीनोपॉज (Menopause) होता है. इस दौरान कई महिलाएं हॉट फ्लैश, वजाइनल ड्राइनेस जैसे लक्षणों का अनुभव करती हैं. ऐसे में महिलाएं राहत पाने के लिए योनि मुद्रा (Womb gesture), हकीनी मुद्रा (Hakini Mudra) और प्राण मुद्रा (Prana Mudra) का अभ्यास कर सकती हैं.

मीनोपॉज (Menopause) मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के खत्म होने और महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हार्मोन (Reproductive hormone) में कमी आने का संकेत है. ज्यादातर महिलाओं को 40 से 50 की उम्र में मेनोपॉज होता है. इसके कारण कई महिलाएं बहुत सारी समस्याओं का सामना करती हैं.

आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मीनोपॉज के कारण महिलाएं हॉट फ्लैश, वजाइनल ड्राइनेस जैसे कुछ लक्षणों का अनुभव करती हैं. कुछ मामलों में नींद में गड़बड़ी भी हो सकती है. कुछ महिलाओं को चिंता या अवसाद भी अपना शिकार बना लेते हैं लेकिन इसके लक्षणों को कम करने के लिए योग का सहारा लिया जा सकता है. आध्यात्मिक गुरु, योग-उद्यमी और लेखक, ग्रैंड मास्टर अक्षर (Grand Master Akshar) के अनुसार, योग एक 'होलिस्टिक सॉल्यूशन' देता है. उनके मुताबिक योग न केवल लक्षणों को आसानी से कम करने में कारगार है, बल्कि इस बदलाव के दौरान योग सपोर्ट सिस्टम भी प्रदान करता है. उन्होंने बताया कि आसन, प्राणायाम और ध्यान के साथ, कुछ मुद्राओं का अभ्यास मीनोपॉज के दौरान मददगार साबित हो सकता है. आइए, जानते हैं कि कौनसी 3 मुद्राएं महिलाओं को करनी चाहिए

महिलाएं जरूर करें इन 3 मुद्राओं का अभ्यास

योनि मुद्रा (Womb gesture)

इसका अभ्यास सुखासन या पद्मासन में बैठ कर किया जा सकता है. इसमें रीढ़ सीधी रहती है.
इसके लिए हाथों को गोद में लेकर आएं.
मिडिल, रिंग और छोटी उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कर लें.
अंगूठे और तर्जनी उंगली को एक साथ दबाएं.
अब हीरे की आकृति बनाते हुए अंगूठे और तर्जनी को एक दूसरे से दूर ले जाएं.

हकीनी मुद्रा (Hakini Mudra)

हकीनी मुद्रा को मन की मुद्रा भी कहा जाता है.
इसे सूर्योदय के दौरान करने की सलाह दी जाती है.
इसका अभ्यास सुखासन या पद्मासन में किया जा सकता है.
इस मुद्रा का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हथेलियों को कुछ इंच की दूरी पर एक दूसरे के सामने लाएं.
दोनों हाथों की उंगलियों और अंगूठों को मिलाएं.
अब हाथों को माथे के पास तीसरे नेत्र चक्र के स्तर तक उठाएं.

यह भी पढ़ें- Women Psychology: प्यार करने वाली औरतों से जुड़े 5 मनोवैज्ञानिक फैक्ट्स

प्राण मुद्रा (Prana Mudra)

इस मुद्रा को दोनों हाथों की मदद से बनाया जाता है.
इसमें रिंग फिंगर के सिरे और छोटी उंगली को अंगूठे के सिरे से जोड़ना होता है.
बाकी सभी अंगुलियों को सीधा फैलाएं.
इस दौरान श्वास लें और श्वास छोड़ें.
क्रोनिक कंडिशन में इसका एक बार सुबह और एक बार शाम को 15 मिनट तक अभ्यास करें.
जानकारी के मुताबिक हर मुद्रा को कम से कम 5 मिनट के लिए करना चाहिए.

Girls Trip? बोरिंग हो जाता है, 8 फन एक्टिविटी से बनाएं यात्रा को मजेदार

अगर आप ये सोच रही हैं कि केवल सहेलियों के साथ ट्रिप मजेदार होगा या नहीं, तो बता दें कि आप कुछ मजेदार एक्टिविटीज़ को शामिल कर गर्ल ट्रिप को काफी मौज-मस्ती से भरा बना सकती हैं.

अगर आप अपनी गर्ल गैंग यानी सहेलियों के साथ कुछ अच्छा और मजेदार वक्त गुजारना चाहती हैं तो एडवेंचरस ट्रिप से बढ़िया कुछ हो नहीं सकता. लड़कियों की यात्रा नई चीज़ों को आज़माने और एक-दूसरे को बेहतर तरीके से जानने और यादगार लम्हें जीने का सबसे अच्छा जरिया हो सकता है. इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ खास आइडियाज़ के साथ ही प्लान बनाएं. मसलन, प्लान ऐसा हो जो आपके बोरिंग ट्रिप को भी मौज-मस्ती से भर दे. यहां हम कुछ ऐसे फन एक्टिविटीज़ से भरपूर आइडियाज़ लेकर आए हैं, जिसे आप अपने अगले गर्ल ट्रिप में आजमाकर उसे यादगार और मजेदार बना सकती हैं.

कॉस्ट्यूम थीम डिनर- मजेदार समय बिताने के लिए आप सभी मिलकर एक कॉस्ट्यूम डिनर प्लान कर सकती हैं. इसके तहत किसी एक थीम पर सभी सजकर खास प्लेस में डिनर प्लान करें, जैसे स्कूल डेज, कसीनो पार्टी या कुछ और.

रेंट पर लें बाइक या कार- आप ऐसी जगह पर जाने का प्लान बना सकती हैं, जहां आप आसानी से रेंट पर बाइक या गाड़ी ले सकें. इसकी मदद से आप अपनी पसंदीदा जगहों और शहर को एक्सप्लोर कर सकेंगी और सहेलियों के साथ मजेदार वक्त गुजारेंगी.

साथ करें कुकिंग- आप एक ऐसा घर बुक करें जहां किचन की व्यवस्था हो. यहां आप कुछ नई रेसिपी ट्राई कर सकती हैं और बेकिंग प्रतियोगिता भी कर सकती हैं. आप साथ में कुकिंग क्लास भी ज्वाइन कर सकती हैं.

स्पा का लें आनंद- सभी सहेलियां मिलकर एक दिन स्पा डे सेलिब्रेट कर सकती हैं. इसके लिए बेहतर होगा कि आप पहले से ही ऐसे स्पा को बुक कर लें, जहां सभी दोस्त एक साथ मालिश, मेनीक्योर, पेडिक्योर, फेशियल आदि करा सकती हों.

जुम्बा क्लास करें ट्राई- अपने वेकेशन के एक या दो दिन आप सभी मिलकर किसी जुम्बा क्लास को ट्राई कर सकती हैं. यकीन मानिये, ये काफी मजेदार होगा. आप चाहें तो योग या सविमिंग क्लास भी साथ में कर सकती हैं.

हाइकिंग करें- आप अपने ट्रिप में एक हाइकिंग एक्टिविटी को भी शामिल करें. पहाड़ों, नदियों और पेड़-पौधों के बीच आप सभी काफी एन्जॉय कर सकती हैं. यहां आप तरह तरह की सेल्फी का मजा भी लें.

इसे भी पढ़ें : वर्किंग वूमन ऑफिस जाने से पहले बैग में जरूर रखें 7 चीजें, कई काम होंगे आसान

पिकनिक करें अरेंज- आप किसी पार्क या खुली जगह में पिकनिक भी अरेंज कर सकती हैं. यहां आप खाने-पीने के अलावा, खुले आसमान के नीचे लेटना, जोर-जोर से गाना, गेम आदि खेलने का आनंद उठा सकती हैं.

शॉपिंग जरूरी- आप लोकल मार्केट में शॉपिंग का प्लान बनाएं और कुछ ऐसी चीजें खरीदें जिसे आप सभी ट्रिप के दौरान साथ में पहनकर घूम सकें. मसलन, एक जैसा टीशर्ट, सनग्लास या एक जैसे जूते आदि.

प्रेग्नेंसी के पूरे 9 महीने रहना है हेल्दी और मेंटली स्ट्रॉन्ग, तो महिलाएं जरूर फॉलो करें ये 10 टिप्स

प्रेग्नेंसी के दौरान थोड़ी सी भी लापरवाही की, तो गर्भ में पल रहे शिशु (Baby) की सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. ऐसे में पूरे 9 महीने एक गर्भवती महिला को अपनी सेहत (Health) के प्रति काफी सावधानी बरतने की जरूरत होती है. डाइट, लाफस्टाइल, एक्सरसाइज आदि का खास ख्याल रखना चाहिए, ताकि आप मेंटली और फिजिकली फिट रहें और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें.

मां बनने का अहसास दुनिया का सबसे खुशनुमा अहसास होता है, लेकिन जरा सी भी लापरवाही बरती जाए, तो प्रेग्नेंसी (Pregnancy) के पूरे नौ महीने तकलीफदायक भी हो सकती है. प्रेग्नेंसी को तीन ट्राइमेस्टर में बांटा गया है, पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही. इसमें पहली और तीसरी तिमाही काफी नाजुक होती है. इस पीरियड के दौरान थोड़ी सी भी लापरवाही की, तो गर्भ में पल रहे शिशु की सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. ऐसे में पूरे 9 महीने एक गर्भवती महिला को अपनी सेहत के प्रति काफी सावधानी बरतने की जरूरत होती है. डाइट, लाफस्टाइल, एक्सरसाइज आदि का खास ख्याल रखना चाहिए, ताकि आप मेंटली और फिजिकली फिट रहें और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें. यहां हम आपको कुछ टिप्स (How to stay fit during pregnancy) बता रहे हैं, जिन्हें फॉलो करके आप खुद को रख सकती हैं हेल्दी और फिट'.

हेल्दी प्रेग्नेंसी के 10 टिप्स

1 टीओआई की खबर के अनुसार, गर्भावस्था के पूरे 9 महीने खानपान में कोई भी लापरवाही ना बरतें. आप जो भी खाएंगी वो आपके शिशु को भी लगेगा. अक्सर, प्रेग्नेंसी के पहले महीने में कुछ महिलाओं को उल्टी, मितली, भूख न लगना, थकान जैसी परेशानियां होती हैं, जिससे उनका खानपान भी गड़गड़ हो जाता है. अपने डाइट में हल्की भुनी पसंदीदा सब्जियों को शामिल करें. फाइबर से भरपूर सब्जियां, फल खाएं. हरी पत्तेदार सब्जियों और फलों के सेवन से आपका शिशु भी हेल्दी होगा.

2 प्रेग्नेंसी के दिनों में शरीर में आयरन की कमी न होने दें. अक्सर महिलाओं के शरीर में आयरन की कमी होती है, जिससे उनमें खून की कमी हो जाती है. वे एनीमिया से ग्रस्त हो जाती हैं. आयरन से भरपूर फूड्स को डाइट में शामिल करें. इसके अलावा, विटामिन सी के साथ आयरन लें ताकि शरीर में आयरन एब्जॉर्प्शन सही हो सके. आप दाल, फल, मीट खाएं. नींबू पानी, संतरा का जूस पीकर भी आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकती हैं.

3 आप खुद को हाइड्रेटेड रखने की कोशिश करें. अपने साथ हमेशा एक बोतल पानी रखें और बीच-बीच में पानी पीती रहें. साथ ही नारियल पानी, स्मूदी, फलों से तैयार जूस और शेक्स भी पी सकती हैं, ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो. डाइट में उन फलों को शामिल करें, जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है. खीरा, खरबूज, टमाटर, लौकी, तरबूजा आदि खाएं, खासकर गर्मी के सीजन में. इतना ही नहीं

4 फॉलिक एसिड का सेवन भी प्रेग्नेंसी के दिनों में बहुत जरूरी होता है. इसे आप हरी पत्तेदार सब्जियों, दालें, फोर्टिफाइड अनाज के सेवन से पा सकती हैं. प्रेग्नेंसी के पहले तीन महीने में आपको फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत होगी, क्योंकि यह भ्रूण को हेल्दी रखने में मदद कर सकता है.

5 दिन भर में हेल्दी स्नैक्स का सेवन करना भी है जरूरी. इसके लिए आप रोस्टेड बादाम, काजू खाएं. ड्राई खुबानी, प्रोटीन बार्स, सीरियल बार्स अपने साथ रखें और थोड़े-थोड़े गैप में खाती रहें.

6 हेल्दी प्रेग्नेंसी तभी संभव है, जब आप प्रतिदिन 7-8 घंटे की नींद लेंगी. सारा दिन काम करके शरीर थक जाता है, ऐसे में आराम करना भी जरूरी है. गर्भवास्था में बायीं करवट लेकर सोएं. बायीं करवट में सोने से शरीर में रक्त प्रवाह सही से होता है और पेट पर दबाव भी कम पड़ता है. एक बात का ध्यान रखें कि आपका बिस्तर और तकिया कंफर्टेबल हो.

7 शारीरिक रूप से एक्टिव रहें, कुछ हल्के एक्सरसाइज, योग करें. प्रतिदिन रात में डिनर करने के बाद 15-30 मिनट टहलें. इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही बना रहेगा. आप फिजिकली और इमोशनली फिट महसूस करेंगी. डिलीवरी के समय अधिक समस्या नहीं होगी.

8 प्रेग्नेंसी के दौरान कुछ चीजों के सेवन से बचना चाहिए जैसे कच्चा या अधपका मांस, कच्चा अंडा, पपीता. उबला अंडा खा सकती हैं, पर ध्यान रखें कि पीला वाला भाग अच्छी तरह से पक गया हो.

9 बहुत ज्यादा किसी बात को लेकर चिंतित या स्ट्रेस में न रहें. इससे मानसिक और शारीरिक सेहत को नुकसान पहुंच सकता है. यदि आपको डिलीवरी के दौरान होने वाली समस्याओं को लेकर अभी से स्ट्रेस, डर बैठ गया है, तो इससे उबरने के लिए योग, डीप-ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें. स्ट्रेस मैनेज करने के लिए टहलें, स्ट्रेचिंग करें.

10 प्रेग्नेंसी के दौरान बहुत अधिक चाय, कॉफी पीने से बचें. कॉफी में मौजूद कैफीन सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. बेहतर है की आप नींबू वाली चाय, हर्बल टी या कैफिन रहित ड्रिंक्स का सेवन करें.

महिलाओं में वजन बढ़ना कई बीमारियों की है वजह, हो सकती हैं ये 8 शारीरिक और मानसिक समस्याएं

सिर्फ मोटापे (obesity) की वजह से लाखों महिलाएं (women) जानलेवा बीमारियों की शिकार हो जाती हैं और जान से हाथ धो बैठती हैं. मोटापे की वजह से हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कैंसर, प्रेग्नेंसी प्रॉब्लम, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. इसलिए जरूरी है कि महिलाएं मोटापे को दूर रखें और सक्रिय रहकर एक्टिव लाइफ लीड करें. आइए जानते हैं कि मोटापे की वजह से महिलाओं को किन शारीरिक (Physical) और मानसिक समस्याओं से दो-चार होना पड़ सकता है.

पुरुषों की तुलना में मोटापे (obesity) की समस्या महिलाओं (women health) में अधिक देखने को मिलती है. मोटापा आमतौर पर चलने फिरने की कमी, असक्रिय लाइफ स्टाइल, अनहेल्दी फूड हैबिट, हार्मोनल बदलाव आदि के कारण हो सकता है. मोटापे के कारण महिलाओं में कई शारीरिक (Physical) और मानसिक (Mental) समस्याएं हो सकती हैं. मोटापे की वजह से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट हेल्थ प्रभावित हो सकती है. जबकि नॉर्मल लाइफ में उन्हें चलने, फिरने, उठने, बैठने और अपने दैनिक कामों में भी परेशानी आ सकती है. यही नहीं, वजन के अनियंत्रित होने से मन और दिमाग पर भी इसका बुरा असर पड़ता है. अधिक मोटापे से महिलाओं में अनिद्रा, तनाव और चिंता जैसी मानसिक समस्याएं देखने को मिलती हैं. साथ ही कई महिलाएं बॉडी शेमिंग की वजह से अपना आत्मविश्वास खो देती हैं.

यूएस वुमंस हेल्थ के मुताबिक, सिर्फ मोटापे की वजह से लाखों महिलाएं जानलेवा बीमारियों की शिकार हो जाती हैं और जान से हाथ धो बैठती हैं. मोटापे की वजह से हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कैंसर, प्रेग्नेंसी प्रॉब्लम, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. इसलिए जरूरी है कि महिलाएं एक्टिव लाइफ लीड करें. आइए जानते हैं कि मोटापे की वजह से महिलाओं को किन शारीरिक और मानसिक समस्याओं से दो-चार होना पड़ सकता है.

महिलाओं में मोटापे से होने वाली समस्याएं

हार्ट संबंधी समस्याएं

दरअसल वजन बढ़ने के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और हाई बीपी के कारण हार्ट अटैक की समस्या भी हो सकती है. इससे शरीर में कई और परेशानियां भी हो सकती हैं और आप जल्दी बीमार पड़ सकते हैं.

डायबिटीज

मोटापे के कारण ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है जिससे टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ता है. यह आपके शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है.

हाई ब्लड प्रेशर

वजन बढ़ने से महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है और ब्लड सर्कुलेशन के लिए हार्ट पर अधिक दबाव पड़ने से हार्ट और रक्त वाहिकाओं दोनों को नुकसान पहुंच सकता है और ब्रेन हैमरेज का खतरा भी हो सकता है.

डिप्रेशन

ज्यादातर किशोरावस्था में लड़कियों में देखा जाता है कि मोटापा बढ़ने से उनमें बॉडी शेमिंग जैसी फीलिंग्स आ जाती है और धीरे-धीरे वे चिंता और डिप्रेशन में चली जाती हैं.

फैटी लीवर प्रॉब्लम

फैटी लीवर में आपके लीवर में फैट बनने लगता है और आपको कई अन्य बीमारियां हो सकती हैं. यह ऑयली फूड, कैलोरी और फ्रूक्टोज के कारण भी हो सकता है. मोटापा और डायबिटीज फैटी लीवर के मुख्य कारणों में से एक है.

किडनी प्रॉब्लम

मोटापे के कारण किडनी में भी परेशानी हो सकती है. इससे ब्लड फिल्टर करने में परेशानी आती है और डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी बढ़ सकती है.

अनिद्रा की समस्या

महिलाओं को कई बार रात में अच्छे से नींद नहीं आती. इसकी वजह बढ़े वजन और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं.

मूड स्विंग

मोटापे के कारण आपके शरीर में कुछ हार्मोनल बदलाव भी आ सकते हैं जिसके कारण मूड स्विंग हो सकता है. कभी-कभी मूड स्विंग होने पर महिलाएं बहुत ज्यादा खाना खाने लगती हैं, जिससे आपकी समस्या और बढ़ सकती है.

ब्रीफ न्यूज

55 लाख रुपये के लिए कश्मीरी को किया किडनैप, 6 घंटे में पुलिस ने पंजाब से किया अरेस्ट

दिल्ली पुलिस ने कश्मीर के रहने वाले एक व्यक्ति के किडनैपिंग केस के 6 घंटे में सुलझा लिया है। पुलिस ने पंजाब पुलिस की मदद से दो किडनैपर्स को महज 6 घंटे के भीतर ही अरेस्ट कर लिया। नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी सागर सिंह कलसी ने इसकी जानकारी दी।

नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने राजधानी से अगवा हुए एक कश्मीरी व्यक्ति को महज 6 घंटे के भीतर ही छुड़वा लिया। पुलिस ने पंजाब पुलिस की मदद से किडनैपर्स को पंजाब के फगवाड़ा से अरेस्ट किया। मामला 55 लाख के रुपये के लेनदेन से जुड़ा था। पीड़ित ने मामले में गिरफ्तार लोगों से पैसे लिए थे जिसे वह अब नहीं लौटा रहा था। इसके बाद से आरोपियों ने उसे अगवा कर पैसे की वसूली का षड्यंत्र रचा था। इस मामले में पुलिस के पास कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई थी। कॉल करने वाले का कहना था कि मेरे जीजा सैयद तारीख को कुछ कश्मीरी लोग कश्मीरी गेट के पास से उठा कर ले गए हैं।

सीसीटीवी फुटेज से हुई पहचान

पीसीआर पर कॉल मिलने के बाद से पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां कोई नहीं था। इसके बाद पुलिस ने आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की। पुलिस को जांच में पता लगा कि कश्मीरी गेट में हरे रामा ट्रैवल्स के पास दो लोग एक व्यक्ति को अगवा कर ले गए हैं। किडनैपर्स ने इसके लिए टैक्सी नंबर की कार का यूज किया था। सीसीटीवी के अनुसार पता लगा कि किडनैपर्स कश्मीरी गेट से जीटी करनाल रोड की तरफ गए हैं। इसके बाद हरियाणा और पंजाब पुलिस को सूचित किया गया। इस क्रम में पंजाब पुलिस के सहयोग से किडनैपर्स को पंजाब के फगवाड़ा के पास से गिरफ्तार किया गया।

छठी से आठवीं तक के छात्रों के लिए शुरू किया जा रहा है द लैंग्वेंज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट

नई दिल्ली। शिक्षा निदेशालय के अनुसार सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भारत की भाषाओं का परिचय देने के लिए द लैंग्वेज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चों को भारतीय भाषाओं को खेल-खेल में समझाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके लिए स्कूलों में छठी से आठवीं तक के बच्चों के लिए द लैंग्वेंज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत बच्चों को शब्दों का खेल जिसमें भाषाओं के विभिन्न लोकप्रिय शब्दों का अर्थ, विभिन्न भाषाओं में पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, स्थानीय क्षेत्रीय पर्वों को मनाना एवं प्रार्थना सभा में उनका महत्व बताना जैसी गतिविधियां कराई जाएंगी। शिक्षा निदेशालय के अनुसार सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भारत की भाषाओं का परिचय देने के लिए द लैंग्वेज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति छठी से आठवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए भाषा सीखने पर जोर देती है।

इस प्रोजेक्ट की गतिविधियों में खेल के रूप में बच्चे हिस्सा ले सकेंगे। यह प्रोजेक्ट छात्रों को भारत की एकता के बारे में समझ पैदा करेगा बल्कि उन्हें भारत की सुंदर सांस्कृतिक विरासत के बारे में भी जागरूक करेगा। इसके तहत होने वाली गतिविधियां आनंददायक होंगी और इसके लिए बच्चों का आकलन नहीं किया जाएगा।

निदेशालय का कहना है कि संबंधित भाषा के शिक्षक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे छात्रों को भारत की विभिन्न भाषाओं में आमतौर पर बोले जाने वाले वाक्यांशों और वाक्यों को जानने में मदद मिलेगी, शास्त्रीय भारतीय भाषाओं की शब्दावली को जानेंगे, अक्षरों और वाक्यों की संरचनाओं को व्यवस्थित करने में भी सक्षम होंगे।

चित्र, पोस्टर से भाषाओं के बारे में बताया जाएगा

प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्कूलों में बच्चों के लिए शब्दों का खेल आयोजित होंगे, जिसमें उन्हें भाषाओं के विभिन्न लोकप्रिय शब्दों के अर्थ शामिल होंगे। वहीं, स्कूलों को स्थानीय क्षेत्रीय पर्वों को मनाना होगा और प्रार्थनासभा में उनका महत्व बताया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न भाषाओं में पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। साथ ही वार्षिक समारोहों के दौरान विभिन्न भाषाओं के चित्र, फोटोग्राफ व नृत्य, संगीत के माध्यम से भाषा के संबंध में बताया जाएगा।

राजधानी में ड्रोन से होगा मच्छरों पर वार, जी-20 के दौरान होने वाली बैठकों वाले स्थानों पर रहेगा फोकस

एनटीवी संवाददाता

मच्छरों का प्रकोप कम करने के लिए एमसीडी ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत ड्रोन से मच्छरों पर और मच्छरजनित इलाके में दवा का छिड़काव किया जाएगा। इससे गर्मी में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से राजधानी वासियों को राहत मिलेगी।

नई दिल्ली। मच्छरों का प्रकोप कम करने के लिए एमसीडी ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत ड्रोन से मच्छरों पर और मच्छरजनित इलाके में दवा का छिड़काव किया जाएगा। इससे गर्मी में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से राजधानी वासियों को राहत मिलेगी। निगम ने तालाबों में मच्छरों के खात्मे के लिए गंबूजिया मछलियों को छोड़ने के साथ जरुरत के हिसाब से फागिंग की तैयारी की है।

दिल्ली नगर निगम के अनुसार जी-20 के मद्देनजर मच्छरों के प्रकोप को रोकने के लिए व्यापक योजना तैयार की गई है। योजना के अनुसार, मच्छरजनित बीमारियों का प्रकोप कम करने के लिए नागरिकों की जागरुकता के लिए विभिन्न बैठकें आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में निर्माण स्थलों, स्मारकों, होटलों, शापिंग माल, प्रसिद्ध बाजारों व आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। उन स्थानों पर विशेष तरह से नजर रखीं जाएगी जहां पर जी-20 के मद्देनजर बैठकें होनी हैं। राजधानी दिल्ली में इस वर्ष मलेरिया के छह तो, डेंगू के 19 और चिकनगुनिया के चार मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। जो कि बीते वर्षों के मुकाबले कम हैं।

हाटस्पाट पर होगी विशेष नजर

मच्छरजनित बीमारियों का प्रकोप कम करने के लिए दिल्ली नगर निगम हाटस्पाट पर विशेष निगरानी भी करेगा। इसके लिए निगम पहले से ही मल्टीटास्किंग स्टाफ को घर-घर जाकर मच्छरों की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए पहले से ही लगा दिया जाएगा। निगम अधिकारी के अनुसार बीते वर्षों के आंकड़े और रिपोर्ट किए गए मरीजों के मामलों के आधार पर संवेदनशील कॉलोनियों/हाट स्पाट की पहचान करेंगे। डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स (डीबीसी) के कार्य की निगरानी सीधे सर्किल-प्रभारी द्वारा की जाएगी। निगम अधिकारी ने बताया कि किसी इलाके में पहले ही ज्यादा मात्रा में मच्छरों की उत्पत्ति की सूचना मिलेगी तो वहां पर विशेष निगरानी की जाएगी।

नगर निगम आयुक्त ने कही ये बात

डेंगू के लिए उत्तरदायी मच्छरों की रोकथाम के लिए हमारी कार्ययोजना पूरे शहर को ध्यान में रखकर बनाई गई है । जी-20 शिखर सम्मेलन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस वर्ष निगम अधिक गहन नियंत्रण उपायों के माध्यम से उच्च सफलता दर सुनिश्चित करेगी। इससे हमें आने वाले वर्षओं में भी लाभ मिलेगा।

-ज्ञानेश भारती, आयुक्त, दिल्ली

किशोर समेत 2 हथियार तस्कर पर दिल्ली पुलिस की दबिश, 10 अवैध हथियार स्पेशल सेल ने किए जब्त

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किशोर समेत दो अंतरराज्यीय हथियार तस्करों को दबोचा है। इनके कब्जे से मध्य प्रदेश निर्मित 10 अवैध हथियार समेत तस्करी में तस्करी में इस्तेमाल अर्टिगा कार जब्त कर ली गई है।

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किशोर समेत दो अंतरराज्यीय हथियार तस्करों को दबोचा है। इनके कब्जे से मध्य प्रदेश निर्मित 10 अवैध हथियार समेत तस्करी में तस्करी में इस्तेमाल अर्टिगा कार जब्त कर ली गई है। अवैध हथियारों में प्वाइंट 30 बोर की चार सेमी-आटोमैटिक पिस्टल, प्वाइंट 32 बोर की दो पिस्टल व चार कट्टा शामिल है। उक्त हथियारों की आपूर्ति तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना गिरोह के बदमाश समेत दिल्ली-एनसीआर के अन्य बदमाशों को की जानी थी, लेकिन इससे पहले दोनों दबोच लिए गए।

डीसीपी स्पेशल सेल आलोक कुमार के मुताबिक एसीपी अतर सिंह, इंस्पेक्टर शिव कुमार व जितेंद्र के नेतृत्व में एसआइ राजेश कुमार की टीम ने शुक्रवार को एनटीपीसी इको पार्क, कालिंदी कुंज-मीठापुर रोड से सिंडिकेट के दो प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनमें एक का नाम मोहम्मद समीर है। वह शाहीनबाग, जामिया नगर का रहने वाला है। 17 वर्षीय किशोर भी शाहीनबाग का रहने वाला है।

मध्य प्रदेश से खरीदे थे हथियार

आलोक कुमार का कहना है कि दोनों ने मध्य प्रदेश के खरगोन से उक्त अवैध हथियारों की खेप खरीदी थी और वे अर्टिगा कार से हथियार लाकर दिल्ली आए थे। उन्होंने खरगोन में एक कुख्यात हथियार निर्माता से हथियार खरीदी थीं और अपने यूपी स्थित एक आका के निर्देश पर दिल्ली में बदमाशों को आपूर्ति करने आए थे। दोनों ने पिछले छह माह के दौरान पिस्टल की तीन और खेप लाने की बात कुबूली है।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे पर बिजली के खंबे से टकराकर पलटा ट्रक, लगी आग; हादसे के बाद Expressway पर लगा लंबा जाम

एनटीवी संवाददाता

वेव सिटी थाना क्षेत्र में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर बुधवार की रात एक ट्रक बिजली के खंभे से टकराकर पलट गया। इस घटना में ट्रक में आग लग गई और एक्सप्रेस वे पर जाम लग गया। हादसे में ट्रक चालक बाल-बाल बच गया।

गाजियाबाद। वेव सिटी थाना क्षेत्र में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर बुधवार की रात एक ट्रक बिजली के खंभे से टकराकर पलट गया। इस घटना में ट्रक में आग लग गई और एक्सप्रेस वे पर जाम लग गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। हादसे में ट्रक चालक बाल-बाल बच गया।

बिजली के खंभे से टकराया ट्रक

बाद में ट्रक को क्रेन से हटवाया गया, तब जाकर यातायात सुचारू हुआ। बुधवार रात करीब 10 बजे वेव सिटी थाना क्षेत्र में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे पर हाईटेक इंजीनियरिंग कालेज के सामने एक ट्रक बिजली के खंबे से टकरा गया और पलट गया। ट्रक पलटते ही उसमें आग लग गई।

हादसे में बाल-बाल बचा ट्रक चालक

यह ट्रक मोहम्मद फिरोज का था। मौके पर पहुंची दमकल की एक गाड़ी ने आग पर काबू पाया। फिरोज ने बताया कि टायर फटने के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर खंबे से टकरा गया था। इस हादसे में चालक बाल-बाल बच गया। हादसे के बाद हाइवे पर जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन से ट्रक को हटवाया और यातायात सुचारू कराया।

संडे मॉर्निंग में कनॉट प्लेस जाने वाले ध्यान दें, कई मार्गों पर वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक

एनटीवी संवाददाता

दिल्ली पुलिस और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी NDMC) 19 फरवरी रविवार को कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में सुबह सात बजे से 10 बजे तक राहगीरी दिवस (Raahgiri Day 2023) का फिर से शुभारंभ कर रहे हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी, NDMC) 19 फरवरी रविवार को कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में सुबह सात बजे से 10 बजे तक ₹राहगीरी दिवस₹ (Raahgiri Day 2023) का फिर से शुभारंभ कर रहे हैं। यह 16 से 22 फरवरी तक होने वाले दिल्ली पुलिस सप्ताह समारोह का हिस्सा है। इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।

ऐसे में कनॉट प्लेस में कार्यक्रम के दिन आउटर सर्कल पर यातायात जाम हो सकता है। दिल्ली यातायात पुलिस ने 19 फरवरी रविवार को सुबह 06.30 बजे से 10.00 बजे तक कनॉट प्लेस की कुछ मार्गों पर यातायात प्रतिबंध लगाए हैं।

इनमेंइनर सर्कल और आउटर सर्कल से इनर सर्कल से कनॉट प्लेस तक प्रवेश करने वाली किसी भी रेडियल सड़क पर किसी भी वाहन को यातायात की अनुमति नहीं दी जाएगी। कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर कहीं भी किसी भी वाहन को रुकने या पार्क करने की अनुमति नहीं होगी।

पार्किंग के लिए वाहन चालकों को बाबा खड़क सिंह मार्ग पर डीएलएफ मल्टीलेवल पार्किंग और आउटर सर्किल पार्किंग स्थल पर ही वाहनों को पार्क करने की सुविधा दी जाएगी।

दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन से सफर करने वाले ध्यान दें, रखरखाव के कारण परिचालन रहेगा बाधित

येलो लाइन (हुडा सिटी सेंटर से समयपुर बादली) के कश्मीरी गेट और विश्वविद्यालय खंड के बीच निर्धारित ट्रैक रखरखाव कार्य किया जाना है। इस कारण सिविल लाइंस और विधानसभा मेट्रो स्टेशन सुबह साढ़े छह बजे तक बंद रहेंगे। उसके बाद इन दोनों स्टेशन यात्रियों के खोल दिए जाएंगे।

नई दिल्ली। येलो लाइन (हुडा सिटी सेंटर से समयपुर बादली) के कश्मीरी गेट और विश्वविद्यालय खंड के बीच निर्धारित ट्रैक रखरखाव कार्य किया जाना है। इस कारण सिविल लाइंस और विधानसभा मेट्रो स्टेशन सुबह साढ़े छह बजे तक बंद रहेंगे। उसके बाद इन दोनों स्टेशन यात्रियों के खोल दिए जाएंगे।

जानें DMRC ने क्या कहा ?

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के अधिकारी का कहना है कि यात्रियों की सुविधा के लिए सुबह साढ़े छह बजे तक कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन और विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के बीच निश्शुल्क फीडर बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। यात्रियों को इसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है।

केंद्र ने लिया वक्फ से 123 संपत्तियों को वापस लेने का फैसला, राष्ट्रपति भवन में भी मौजूद है संपत्ति

केंद्र सरकार ने दिल्ली में 123 वक्फ संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है। ये संपत्तियां कनाट प्लेस अशोक रोड मथुरा रोड समेत राष्ट्रीय राजधानी के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर है। इनमें मस्जिद दरगाह और कब्रिस्तान तक शामिल हैं।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिल्ली में 123 वक्फ संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है। ये संपत्तियां कनाट प्लेस, अशोक रोड, मथुरा रोड समेत राष्ट्रीय राजधानी के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर है। इनमें मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान तक शामिल हैं। एक संपत्ति राष्ट्रपति भवन परिसर के भीतर भी मौजूद है।

जानें पूरा मामला

कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की सरकार ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले वर्ष 2014 में इन संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड के नाम करने का फैसला किया था, जिसे लेकर यूपीए सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा था। केंद्र सरकार को इस फैसले को ऐतिहासिक व राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सरीखा बताते हुए कहा कि संभवत देश में यह पहला मामला है, जब सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए एक अराजनैतिक संगठन ने इतना लंबा संघर्ष किया हो। इस मामले को इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ही कोर्ट ले गई थी। विहिप के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने इस जीत पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि विहिप ने इसे लेकर करीब 40 साल तक संघर्ष किया है, जिसका सुखद परिणाम सामने आया है।

इन संपत्तियों को वापस लेने का फैसला केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय ने किया है। मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर केंद्र सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एसपी गर्ग की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय समिति गठित की गई थी, जिसके सामने गैर-अधिसूचित वक्फ संपत्तियों के मुद्दे पर दिल्ली वक्फ बोर्ड से कोई प्रतिनिधित्व या आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी, जबकि उसे दो मौके दिए गए थे, लेकिन उसकी ओर से कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। ऐसे में इन संपत्तियों को वापस लेने का फैसला किया गया है और इसकी जानकारी वक्फ बोर्ड को पत्र लिखकर दे दी गई है। वैसे, अभी ये संपत्तियां मुस्लिम समुदाय के कब्जे में है।

अब भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएनडीओ) इन संपत्तियों का सर्वेक्षण कर आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा।

हालांकि, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतउल्ला खान ने इस तरह की नोटिस से इंकार करते हुए मंत्रालय पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पहले से ही यह मामला हाई कोर्ट में लंबित है, जिसका नंबर 1961/2022 है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह केंद्र सरकार को इन वक्फ संपत्तियों का किसी तरह का कब्जा नहीं होने देंगे।

वर्ष 1984 से चल रहा था मामला

यह मामला वर्ष 1984 से लंबित है। तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को सौंपने का फैसला लिया था। तब भी इंद्रप्रस्थ विहिप इस मामले को लेकर कोर्ट में गई थी। तब हाई कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया था, लेकिन वर्ष 2014 में एक बार तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने लोकसभा चुनाव की घोषणा के कुछ घंटे पहले ही इन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को सौंपने का आदेश दिया, जिसे चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन माना और उस आदेश को खारिज कर दिया था। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने बताया कि इन संपत्तियों पर मुस्लिम समुदाय का कब्जा पहले से था। इसलिए हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर वे लोग गए थे।

हवा की रफ्तार थमते ही खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया प्रदूषण, शुक्रवार को गाजियाबाद का AQI 350 पहुंचा

एनटीवी न्यूज

दिल्ली-एनसीआर में तेज हवा की रफ्तार थमने के तुरंत बाद गाजियाबाद में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। शुक्रवार का जिले का एक्यूआई 350 दर्ज किया गया है। वहीं प्रशासन की ओर से प्रदूषण की रोकथाम में लापरवाही बरती जा रही है।

गाजियाबाद। हवा की रफ्तार थमते ही जिले में प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। शुक्रवार को गाजियाबाद का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 350 दर्ज किया गया, जबकि बृहस्पतिवार को जिले का एक्यूआइ 232 दर्ज किया गया था। जिले में शुक्रवार को वसुंधरा इलाका सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा। यहां का एक्यूआइ 397 दर्ज किया गया। लोनी का एक्यूआइ 383, संजय नगर का 315 और इंदिरापुरम का एक्यूआइ 306 दर्ज किया गया।

तेज हवा से मिली थी राहत

बीती 12 फरवरी से तेज हवा चलने के कारण जिले में लोगों को प्रदूषण से राहत मिली थी। दरअसल जिले में हो रहा प्रदूषण तेज हवा के साथ आगे बह जा रहा था। इससे प्रदूषण का स्तर नहीं बढ़ रहा था। अब हवा की रफ्तार थमते ही प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ने लगा है। बृहस्पतिवार को एक्यूआइ 232 था। शुक्रवार को एक्यूआइ 350 पहुंच गया।

जिले में इन कारणों से हो रहा प्रदूषण

जिले के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में 90 प्रतिशत सड़कें टूटी हुई हैं। मुख्य मार्गों की भी सड़कों में जगह-जगह गड्ढे हैं। ऐसे में सड़कों पर जाम लगता है और जाम में फंसे वाहन धुआं उगलते हैं। नगर निकाय की ओर से सड़कों से धूल की सफाई कर पानी के छिड़काव में लापरवाही बरती जा रही है। जगह-जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं। बिना ढके बड़े वाहनों से कूड़ा एक से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। प्रदूषण की रोकथाम में लापरवाही बरती जा रही है। इन सब कारणों से जिले में प्रदूषण हो रहा है। जिले में वसुंधरा इलाका सबसे ज्यादा प्रदूषित बना हुआ है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक यहां पर रैपिड ट्रेन का स्टेशन बन रहा है। इस कारण ज्यादा प्रदूषण हो रहा है।

बीते कुछ दिन का एक्यूआइ

तारीख एक्यूआइ

16 फरवरी 232
15 फरवरी 151
14 फरवरी 118
13 फरवरी 132
12 फरवरी 159

(नोटः एक्यूआइ 50 से 100 तक संतोषजनक माना जाता है)

सड़कों की सफाई और पानी का होगा छिड़काव

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी उत्सव शर्मा ने बताया कि जिले में प्रदूषण की रोकथाम को लेकर ग्रेप के नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। नगर निकायों को सड़कों की सफाई करने और पानी का छिड़काव करने की जिम्मेदारी दी गई है।

ब्रीफ न्यूज

हाइपर सुपर मार्केट की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर की करोड़ों की ठगी, ED ने दर्ज किया मनी लांड्रिग का केस

हाइपर सुपर मार्केट की फ्रेंचाइजी देकर ठगी करने वाला गिरोह कोरोना से पहले से पहले सक्रिय हुआ था। गिरोह में शामिल आरोपितों ने हाइपर मार्ट की फ्रेंचाइजी के अलावा मिडवे कैफे वेस्टलैंड साउथ लैंड डच फ्रंस्टर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बनाकर सैकड़ों लोगों से पैसे ले लिए थे।

नोएडा। हाइपर सुपर मार्केट की फ्रेंचाइजी देकर ठगी करने वाला गिरोह कोरोना से पहले से पहले सक्रिय हुआ था। ठगी के गिरोह में शामिल आरोपितों ने हाइपर मार्ट की फ्रेंचाइजी के अलावा मिडवे कैफे, वेस्टलैंड, साउथ लैंड, डच फ्रस्टर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बनाकर सैकड़ों लोगों से पैसे ले लिए थे। गिरोह के सरगना ने 20 से अधिक आइडी अलग-अलग नाम से बना रखी थी। आरोपितों ने फर्जी कंपनियों की वेबसाइट भी बनवाई थी। जिस पर रिटेल स्टोर की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर लोगों से 30 से 50 लाख रुपये तक लेते थे।

करीब 500 लोगों से ठगी

गिरोह ने करीब 500 से अधिक लोगों से करोड़ों की ठगी की है। जब फ्रेंचाइजी नहीं मिलने पर लोगों ने पैसे मांगने शुरू किए तो आरोपितों ने सेक्टर-63 का आफिस बंद कर दिया था। नोएडा में फ्रेंचाइजी देकर ठगी करने वाला गिरोह वर्ष 2019 से 2020 तक सक्रिय था। करीब एक साल में जालसाजों ने पूरे एनसीआर समेत आधे दर्जन से अधिक राज्यों में अपना नेटवर्क फैलाया। हाइपर सुपर मार्केट की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली नोएडा की वेस्टलैंड ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, हाइपर सुपर मार्केट कंपनी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। निवेशकों के साथ करीब दस करोड़ रुपये से अधिक की में नोएडा पुलिस ने आठ मुकदमे भी दर्ज किए थे।

बिल्डिंग किराए पर ली

लखनऊ स्थित ईडी के जोनल कार्यालय ने नोएडा पुलिस से जानकारी जुटाने के बाद प्रारंभिक जांच की। जिसमें आरोप सही पाए जाने पर कंपनी के निदेशकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। गिरोह के सरगना राजेश ने अपने भाई अंकुर व अन्य साथियों के साथ सेक्टर-63 के ई-29 में एक बिल्डिंग किराए पर ली थी। आरोपितों ने हाइपर मार्ट की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर ठगी शुरू कर दी।

अन्य राज्यों में शिकायत

जालसाजों के खिलाफ उत्तरप्रदेश के अलावा कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, मध्यप्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी शिकायत हो चुकी थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर फटकार लगाते हुए गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सीबीआई, ईडी और सीरियस फ्राड इंवेस्टीगेशन आफिस को नोटिस जारी किया था।

लाखों में कैश और महंगी कार समेत सामान बरामद

वहीं फेज-3 कोतवाली में भी आरोपितों के खिलाफ ठगी का शिकार लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर मर्सिडीज समेत पांच कार, सवा तीन किलोग्राम सोने के बिस्किट, आभूषण, 13.5 लाख रुपये नकद सहित करीब दस करोड़ रुपये का माल बरामद किया था। 60 लाख रुपये खातों में फ्रीज कराए गए थे।

हर हर महादेव से गूंजे ट्रांस हिंडन क्षेत्र के शिवालय, मंदिरों के बाहर लगी शिव भक्तों की लंबी कतार

महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शनिवार को शिवालय व मंदिर हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे। शिव भक्त रुद्रभिषेक के बाद शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। ट्रांस हिंडन क्षेत्र के मोहन मंदिर पर महाशिव रात्रि पर सबसे अधिक भीड़ होती है।

साहिबाबाद। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शनिवार को शिवालय व मंदिर हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे। शिव भक्त रुद्रभिषेक के बाद शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। मोहन नगर मंदिर और कैलास मानसरोवर भवन में भक्तों की भारी भीड़ है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस तैनात है। ट्रांस हिंडन क्षेत्र के मोहन मंदिर पर महाशिव रात्रि पर सबसे अधिक भीड़ होती है। भीड़ को देखते हुए शुक्रवार को ही सभी तैयारी पूरी कर लई गईं थीं। सुबह तड़के ही इस मंदिर में भक्तों की कतार लग गई। इसके अलावा शिप्रा सनसिटी के शिव हनुमान मंदिर, शिप्रा रिवेरा के प्राचीन हनुमान मंदिर में भी बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे हैं।

भोलेनाथ का श्रंगार भी किया

की प्राचीन सनातन धर्म मंदिर, पार्श्वनाथ पैराडाइज स्थित श्री शिव शक्ति मंदिर सहित अन्य मंदिरों में प्रातः रुद्राभिषेक किया गया। मंदिरों में लोग जलाभिषेक व पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। विश्व कल्याण के लिए मंदिरों में पूजा की जा रही है। शाम के समय लोग लोग कीर्तन व आरती करेंगे। कैलाश मानसरोवर भवन में जलाभिषेक एवं भगवान भोलेनाथ का श्रंगार और अभिषेक किया गया।

लोनी और खोड़ा में भी हुआ जलाभिषेक

लोनी तिराहा स्थित शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर, बंथला चिरोड़ी मार्ग स्थित मोक्ष धाम मंदिर, बार्डर जल वाला मंदिर सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई। नगर पालिका के कर्मचारियों ने सुबह से ही मंदिरों के बाहर सफाई करने में लगे रहे। मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लाइन लगी रही।

पुलिस कर रही निगरानी

मंदिर के गेट पर पुलिस की तैनाती की गई है। कुछ पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में भी तैनात हैं। मंदिरों के पास संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। अधिकारी मंदिरों का लगातार निरीक्षण करते रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों से व्यवस्था देखी जा रही है।

ऑनलाइन सट्टेबाजी में झांसी फ्रेंचाइजी का सरगना को कोर्ट ने भेजा जेल, कई देशों से जुड़े थे आरोपी के तार

नोएडा के सेक्टर-108 स्थित कोठी में महादेव बुक एप के माध्यम से नोएडा में ऑनलाइन सट्टेबाजी का गिरोह संचालित कर रहे झांसी फ्रेंचाइजी के सरगना सचिन सोनी को सेक्टर-39 कोतवाली पुलिस ने कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

नोएडा। सेक्टर-108 स्थित कोठी में महादेव बुक एप के माध्यम से नोएडा में ऑनलाइन सट्टेबाजी का गिरोह संचालित कर रहे झांसी फ्रेंचाइजी के सरगना सचिन सोनी को सेक्टर-39 कोतवाली पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपित अंतरराष्ट्रीय गेमिंग फ्राड गिरोह का इंडिया का हेड है। आरोपित ने सेक्टर-168 स्थित द गोल्डन पाम सोसायटी में किराये पर फ्लैट ले रखा था, जहां से आरोपित ऑनलाइनसट्टेबाजी के गिरोह पर नजर बनाए रखता था। पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर एक विभिन्न जगह पर दबिश देकर एक लैपटाप, एक स्मार्ट फोन, पांच फर्जी आधार कार्ड, कोठी का अनुबंध बरामद किया है। गिरोह में शामिल 16 सदस्यों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। आरोपित ने अपने झांसी के तीन साथी अंसफ, आरिफ मंसूरी व नीरज गोस्वामी के नाम भी बताए। नोएडा पुलिस को उसने पूछताछ के दौरान बताया कि अंसफ की झांसी में बहुत प्रापर्टी है। पुलिस उसके बयान को क्रास चेक कर रही है। भोपाल के निक्की गुप्ता के गिरोह में शामिल होने की बात कही है। आरोपित इंडिया हेड के तौर पर नोएडा का काम देखता था। वहीं, नीरज गोस्वामी मैनेजमेंट देखता था। नीरज अभी बैंकाक में है। नीरज का दुबई में बैठे मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर से संबंध है। जेल जा चुके आरोपित अलग-अलग शिफ्ट में काम करते थे।

एलिवेटेड रोड पर डिवाइडर से टकराई अनियंत्रित कार, हादसे में युवती की मौत

एनटीवी

नोएडा स्थित एलिवेटेड रोड पर बीते रात एक अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकरा गई। कार चला रही युवती की हादसे में मौत हो गई है। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने के बाद फिर मृतक के शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।

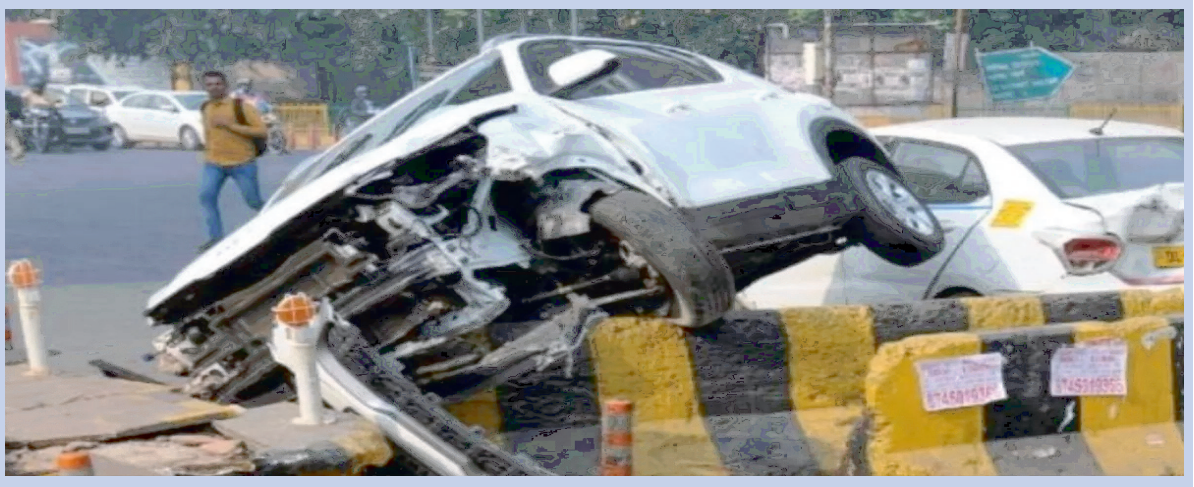

नोएडा। नोएडा के सेक्टर-24 कोतवाली क्षेत्र स्थित एलिवेटेड रोड पर शुक्रवार देर रात एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। कार सवार एक युवती की हादसे में मौत हो गई, जबकि पांच अन्य युवक-युवतियों को मामूली चोट आई है। घायलों का नजदीक के अस्पताल में उपचार चल रहा है। मृतक युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घायलों के स्वजन को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। मृतक युवती की पहचान ग्वालियर के दर्पण कालोनी की भूमिका जादौन के रूप में हुई है, जो नोएडा स्थित एक कंपनी में काम करती थी। घटना के बाद अल्प समय के लिए यातायात भी बाधित रहा। क्षतिग्रस्त कार को पुलिस ने सड़क के किनारे कर यातायात को सामान्य कराया। देर रात सेक्टर-18 में पार्टी करने के बाद सेक्टर-62 की तरफ जा रहे थे कार सवार। घटना के समय सभी लोगों के नशे में होने की बात कही जा रही है। शुक्रवार रात साढ़े 12 बजे हुआ हादसा।

छोटा भाई करता था लूट, बड़ा खपाता था माल; साथी सहित दोनों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

इंदिरापुरम कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को दो सगे भाईयों सहित तीन बदमाशों को गिरफ्तार करके प्रवासी भारतीय महिला के साथ हुई लूट समेत सात वारदात का राजफाश किया है। पूछताछ के बाद आरोपितों को जेल भेज दिया है।

गाजियाबाद। इंदिरापुरम कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को दो सगे भाईयों सहित तीन बदमाशों को गिरफ्तार करके प्रवासी भारतीय महिला के साथ हुई लूट समेत सात वारदात का राजफाश किया है। पूछताछ के बाद आरोपितों को जेल भेज दिया है। पूछताछ में आया है कि छोटा भाई साथी के साथ मिलकर लूट व वाहन चोरी करता था। बड़ा भाई माल को खपाता था।

जानें पूरा मामला

सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि बाइक सवार दो लुटेरों ने नौ फरवरी को इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र के नीति खंड-एक में प्रवासी भारतीय पारूल गुप्ता से करीब पांच लाख के गहने व महंगी घड़ी और चश्मा लूटा था।

पुलिस की चार टीमें इस मामले में काम कर रही थीं। टीमों ने करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। उसमें अहम साक्ष्य मिले। उसके आधार पर शुक्रवार को मंगल चौक के पास से तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। उनकी पहचान मूल रूप से मुजफ्फरनगर, बिहार के अशरफ उर्फ राज उर्फ मोटा उर्फ नानू और अकरम व भागलपुर, बिहार के सिंकू के रूप में हुई। पूछताछ में पता चला कि अशरफ व अकरम सगे भाई हैं। तीनों यहां कनावनी में किराए के मकान में रहते हैं।

17 साल की उम्र में की पहली चोरी

स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि अकरम बड़ा और अशरफ छोटा है। अशरफ ने 17 साल की उम्र में जनवरी-2020 में इंदिरापुरम से बाइक चोरी की थी। उसे बाल सुधार गृह भेजा गया था। तीन माह बाद वह बाहर आया था। अक्टूबर 2020 में उसने फिर से बाइक चोरी की। वह बाल सुधार गृह भेजा गया। बाहर आने पर फिर बाइक चोरी। अक्टूबर 2022 में उसे जेल भेजा गया। जमानत पर आने के बाद वह सिंकू के साथ मिलकर लूट करने लगा। उसने इंदिरापुरम में चार और कौशांबी में दो लूट की। इंदिरापुरम से बाइक चोरी की।

सराफ ने दिखाई जागरूकता

स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि प्रवासी भारतीय पारूल से लूट के बाद अकरम गहने बेचने सराफ को गहने बेचने गया। उसने आधार कार्ड की छाया प्रति लेकर गहने खरीदे। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की जांच करते हुए सराफ की दुकान तक पहुंची तो मामला खुला। दुकान के सीसीटीवी कैमरे में अकरम की गहने बेचते की फुटेज कैद थी। पुलिस ने उसे साक्ष्य के लिए अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस सराफ को सरकारी गवाह बनाएगी।

अकरम खपाता था माल

अशरफ ने बताया कि वह सिंकू के साथ लूट व चोरी करता था। बड़ा भाई अकरम चोरी व लूट के माल को खपाता था। माल बेचने से मिलने वाले रुपयों को तीनों आपस में बांट लेते थे। पहली बार चोरी की बाइक बेचने से पैसा मिला तो लालच आ गया। उसके बाद लगातार चोरी व लूट करने लगा। स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि इस गिरोह में अन्य बदमाश भी हो सकते हैं। इसकी जांच की जा रही है।

ऑटो इंडस्ट्री के लिए कैसा रहा ये सप्ताह ? जानिए कौन-सी गाड़ियां हुईं लॉन्च

पॉपुलर बाइक से लेकर किफायती कार तक। इस सप्ताह ऑटो सेक्टर में कई गाड़ियां लॉन्च हुई हैं जिसका जिक्र हम इस खबर के माध्यम से करने जा रहे हैं। आइये पढ़ते हैं इस हफ्ते क्या कुछ रहा खास

नई दिल्ली। यह सप्ताह ऑटो इंडस्ट्री के लिए खास रहा है। क्योंकि, इस सप्ताह में कुछ खास गाड़ियां लॉन्च हुई हैं। इसका अलावा, एक फेमस ब्रांड ने अपनी पॉपुलर बाइक को भी नया अपडेट दिया है। आइये जानते हैं इस सप्ताह लॉन्च होने वाली गाड़ियों के बारे में

1. Audi Q3 sportback

ऑडी (Audi) ने भारत में नई क्यू3 स्पोर्टबैक कूप एसयूवी (Q3 Sportback Coupe SUV) को लॉन्च कर दिया है। यह अपने सेगमेंट की पहली कूपे एसयूवी है, जिसमें 220 किमी प्रति घंटे की जबरदस्त स्पीड के साथ एक स्पोर्ट कार के सारे गुण देखने को मिलते हैं।

2. 2023 Yamaha FZ-X, R15 V4, MT-15 V2 launched

दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी यामाहा भारतीय ऑटो बाजार में अपनी तीन शानदार बाइक्स के साथ धूम मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बाइक निर्माता ने अपनी तीन अपडेटेड बाइक्स R15 V4, MT 15 और FZ-X आज लॉन्च कर दिया है। ये मॉडल्स 150cc सेगमेंट में आने वाले हैं और नए फीचर्स के तौर पर कई शानदार फीचर्स के साथ लाया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि इन बाइक्स में किन फीचर्स को शामिल किया जा रहा है।

3. Mercedes-Benz reopens bookings for G63 AMG and GLS 600 Maybach

मर्सिडीज बेंज ने अपनी पावरफुल एसयूवी मायबैक जीएलएस 600 के साथ ही ऑफ रोडर एएमजी जी63 की बुकिंग फिर से शुरू करने का ऐलान हाल ही में किया था। इसके साथ ही अब AMG G63 पर वेटिंग पीरियड 16 महीने और Maybach GLS 600 पर वेटिंग पीरियड 10 महीनों तक का हो गया है।

4. 2023 Hyundai Verna

काफी लंबे समय से इंतजार की जा रही नए जनरेशन की हुंडई वरना (Nex Gen Hyundai Verna 2023) अगले महीने दस्तक देने वाली है। नई वरना को 21 मार्च को लॉन्च किया जा रहा है। केवल पेट्रोल वर्जन में लाई जाने वाली ये सेडान कार का टीजर पहले ही जारी कर दिया गया था, जिसमें इसके फीचर्स की जानकारी मिलती है। वहीं, इसे बुक करने के लिए 25,000 रुपये की टोकन मनी रखी गई है। कहा जा रहा है कि नई वरना को चार ट्रिम्स में लाया जा सकता है।

5. Maruti Suzuki Ciaz launched with new features

Maruti Suzuki Nexa ने भारत में Ciaz को एक नए डुअल-टोन कलर ऑप्शन में लॉन्च किया। टॉप-स्पेक अल्फा वेरिएंट पर आधारित मारुति सुजुकी सियाज डुअल-टोन मैनुअल वेरिएंट की कीमत 11.15 लाख रुपये है, जबकि ऑटोमैटिक वेरिएंट 12.35 लाख रुपये (दोनों कीमतें एक्स-शोरूम) हैं। अगर आप इस कार को खरीदना चाहते हैं तो अपने आस-पास के नेक्सा शोरूम में जाकर 2023 सियाज को खरीद सकते हैं।

ब्रीफ न्यूज

देखते ही देखते लोगों की पहली पसंद बन गया ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, इसे खरीदने टूट पड़े लोग

नई दिल्ली. भारतीय बाजार में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल ना सिर्फ लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं, बल्कि इनकी सेल्स के आंकड़ों में भी रिकॉर्ड ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले महीने 30 अक्टूबर तक 68,234 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की सेल्स हुई। इस तरह इसमें 29% की रिकॉर्ड मंथली ग्रोथ देखने को मिली। इस ग्रोथ से ये बात साफ है कि अब लोगों को भरोसा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की तरफ बढ़ रहा है। पिछले 2-3 महीनों के दौरान इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर में आग लगने के मामले भी सामने नहीं आए हैं, जिससे ये भरोस मजबूत हो रहा है। पिछले महीने ओला इलेक्ट्रिक को 53% की मंथली ग्रोथ मिली।

ओला इलेक्ट्रिक ने 15095 यूनिट बेचीं

ओला इलेक्ट्रिक अक्टूबर 2022 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बेचने वाली कंपनी बनी। उसने बीते महीने 53% की मंथली ग्रोथ के साथ 15,095 यूनिट बेचीं। लिस्ट में दूसरे नबंर पर ओकिनावा रही। इसने 38% की मंथली ग्रोथ के साथ 11,754 यूनिट सेल कीं। तीसरे नंबर पर एम्पीयर रही। इसने 36% की मंथली ग्रोथ के साथ 8812 यूनिट बेचीं। टीवीएस मोटर्स को 31% और बजाज ऑटो को 26% की मंथली ग्रोथ मिली। जबकि एथर एनर्जी को 11% की मंथली ग्रोथ मिली।

सितंबर में भी ओला इलेक्ट्रिक रही नंबर-1

सितंबर में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की 52,957 यूनिट्स बिकीं। जबकि अगस्त में ये आंकड़ा 50,474 यूनिट्स का था। यानी हर महीने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में ग्रोथ दिख रही है। सिंतबर 2022 में ओला इलेक्ट्रिक ने 9,616 इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे। कंपनी नवरात्रि-दशहरा ऑफर के चलते अपने ई-स्कूटर पर 10 हजार रुपए का डिस्काउंट दे रही थी। जिसके चलते इसे फायदा मिला। अक्टूबर में भी फेस्टिवल ऑफर के चलते ओला इलेक्ट्रिक को फायदा मिला।

ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के फीचर्स

3 सेकेंड में 0 से 40 km की स्पीडः ओला ने S1 स्कूटर में 8.5 किलोवॉट पीक पावर जनरेट करने वाली मोटर लगाई गई है। इस मोटर को 3.9 किलोवॉट कैपेसिटी वाली बैटरी से जोड़ा गया है। ये 0 से 40 किलोमीटर की स्पीड सिर्फ 3 सेकेंड में पकड़ लेता है। इसकी टॉप स्पीड 115 किमी प्रति घंटा है। सिंगल चार्ज पर ये 181 किमी तक की रेंज देता है। इसमें राइडिंग के लिए नॉर्मेल, स्पोर्ट और हाइपर मोड मिलते हैं।

6 घंटे में फुल चार्जः स्कूटर के साथ कंपनी 750 वॉट का पोर्टेबल चार्जर देगी। इसकी मदद से बैटरी 6 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। वहीं, ओला के हाइपरचार्जर स्टेशन पर 18 मिनट में 50% बैटरी चार्ज करा सकते हैं।

रिवर्स मोड भी मिलेगाः स्कूटर में रिवर्स मोड भी मिलेगा। इसकी मदद से गाड़ी को पार्किंग में लगाने में आसानी होगी। यदि किसी चढ़ाई वाली जगह पर स्कूटर को

2023 Toyota Innova Crysta diesel भारतीय बाजार में जल्द देगी दस्तक

2023 Toyota Innova Crysta को चार वेरिएंट्स G GX VX और ZX में पेश करेगी। इस कार का डिजाइन काफी दमदार है। इसके फ्रंट-एंड को अपडेट किया गया है। सामने वाला बंपर बिल्कुल नया है जिसमें थोड़ा नया शेप दिया जा सकता है।

नई दिल्ली। Toyota Kirlsokar Motor ने पिछले साल कुछ समय के लिए इनोवा क्रिस्टा को बंद कर दिया था, ठीक नई-जनरेशन इनोवा हाई क्रॉस के लॉन्च के आसपास। हालांकि वाहन निर्माता कंपनी ने पुष्टि की थी कि क्रिस्टा को हाई क्रॉस के साथ बेचा जाना जारी रहेगा। 2023 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा ने बाजार में अपनी आधिकारिक शुरुआत कर दी है, आने वाले दिनों में लॉन्च होने की उम्मीद है। एमपीवी में पहले पेश किए गए मॉडल की तुलना में काफी बदलाव किया गया है।

2023 Toyota Innova Crysta diesel

2023 इनोवा क्रिस्टा को केवल डीजल इंजन के साथ पेश किया जाएगा, जिसमें 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन अब बंद कर दिया गया है। अपडेटेड इनोवा क्रिस्टा केवल 2.4-लीटर चार-सिलेंडर डीजल इंजन के साथ आएगी । इस इंजन को पहले 150 पीएस/360 एनएम पर रेट किया गया था। इसके इंजन को 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, इंजन को आगामी भारत स्टेज 6 (बीएस6) चरण 2 आरडीई मानदंडों के अनुरूप भी बनाया जाएगा।

2023 Toyota Innova Crysta

डिजाइन

इस कार का डिजाइन काफी दमदार है। इसके फ्रंट-एंड को अपडेट किया गया है। सामने वाला बंपर बिल्कुल नया है जिसमें थोड़ा नया शेप दिया गया है। फॉग लैंप और टर्न इंडिकेटर को भी नया रूप दिया गया है, दोनों के चारों ओर एक नई एल-आकार की क्रोम पट्टी है। डुअल-टोन अलॉय व्हील सहित साइड प्रोफाइल में कोई बदलाव नहीं किया गया है।2023 इनोवा क्रिस्टा एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, एयरबैग, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर,हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे शानदार फीचर्स है।

2023 Toyota Innova Crysta कीमत

2023 Toyota Innova Crysta को चार वेरिएंट्स G, GX, VX और ZX में पेश करेगी। कंपनी ने कार के लिए 50,000 रुपये में बुकिंग लेना शुरू कर दिया है। डीजल इनोवा क्रिस्टा की कीमत लगभग 19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है।

इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाते हैं तो समझे बैटरी खराब होने के ये संकेत

अगर आपको ये पता लगाना है कि कार या स्कूटर की बैटरी खराब तो नहीं हो रही है तो इसका पता लगाना काफी आसान है। आप इन संकेतों को समझकर अपनी इलेक्ट्रिक कार को खराब से होने से पहले ही बचा सकते हैं।

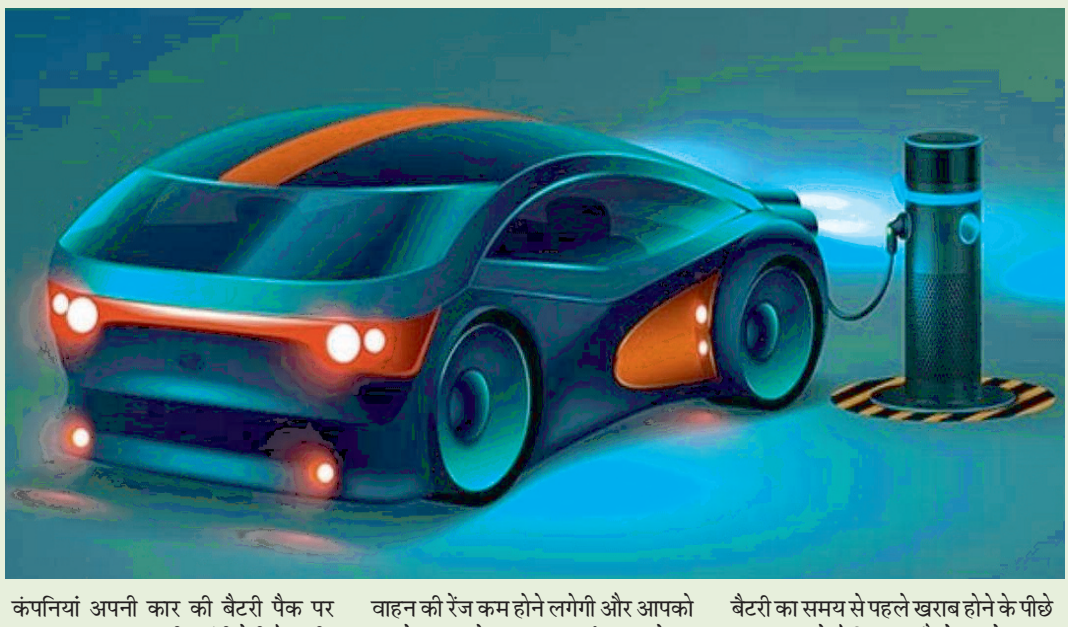

नईदिल्ली। भारतीय बाजार में दिन पर दिन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत ने लोगों की कमर तोड़ दी है। जिसके कारण इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड तेजी से बढ़ते जा रही है। इसके लिए सरकार भी अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रही है ताकि अधिक से अधिक लोग ईवी को लेकर जागरूक हो सके। लेकिन आज भी ईवी से जुड़ी कई बड़ी समस्याएं है जिसमें से एक सबसे बड़ी समस्या चार्जिंग स्टेशन।

जिस तरह से हर जगह आपको पेट्रोल पंप मिलेंगे उसी तरीके से ईवी चार्जिंग स्टेशनों की कमी है। जिस पर कई बड़े वाहन निर्माता कंपनियां काम कर रही है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार हैं तो आपको इन बातों का जानना काफी जरूरी है। कार की बैटरी कब खराब होगी या फिर खराब होने से पहले कैसे संकेत देती है।

कार की बैटरी कितने साल चलेगी

आपको बता दे लगभग सभी वाहन निर्माता कंपनियां अपनी कार की बैटरी पैक पर लगभग 8 साल तक की वारंटी देती है। वहीं, अगर आप इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इसे 10 साल तक भी चला सकते हैं। दो पहिया वाहन की बैटरी पैक लगभग 3 से 5 साल तक की होती है।

बैटरी खराब तो नहीं हो रही है

अगर आपको ये पता लगाना है कि कार या स्कूटर की बैटरी खराब तो नहीं हो रही है तो इसका पता लगाना काफी आसान है। ये अचानक से खराब नहीं होती है। खराब होने से पहले ये कई संकेत देती है। जिसके बाद बैटरी धीरे- धीरे खराब होती है । तब आपके वाहन की रेंज कम होने लगेगी और आपको अपने वाहन को बार -बार चार्ज करना होगा। रेंज के कारण आप आराम से पता लगा सकते हैं कि बैटरी खराब है या नहीं।

कितनी होती है इसकी लागत

ईवी की बैटरी पैक काफी अधिक महंगी होती है। अगर वो वारंटी के अंदर नहीं है और डैमेज है, आपको इसपर कई हजारों का खर्च करना पड़ सकता है। कार के बैटरी पैक की बात करें तो इसकी कीमत लाखों तक की होती है, वहीं स्कूटर दो पहिया वाहन में इसकी कीमत हजारों तक की होती है।

क्या होता है खराब होने का कारण

बैटरी का समय से पहले खराब होने के पीछे का कारण ये है कि आप कैसे अपने वाहन को चार्ज कर रहे हैं। फास्ट चार्जर के अधिक इस्तेमाल से बैटरी की लाइफ खराब हो जाती हौ। वहीं बैटरी को पूरी तरह से डिस्चार्ज करने या फिर हर बार 100 फीसदी चार्ज करने से भी बैटरी की लाइफ कम हो जाती है । ईवी बैटरी को 15 परसेंट तक पहुंचने पर चार्ज किया जाना चाहिए। जब कि इसे 80 से 85 प्रतिशत तक चार्ज करना चहिए। बैटरी पर मौसम का भी काफी प्रभाव पड़ता है । इसके कारण भी बैटरी समय से पहले खराब हो सकती है।

तिरछी क्यों डिजाइन की जाती है कार की विंडस्क्रीन, जानिए क्या है इसकी अहमियत

नई दिल्ली। अगर आप कार और बस दोनों से ट्रैवल करते हैं तो आपने इसे जरुर गौर किया होगा कि कारो की विंडस्क्रीन तिरछी होती है और बसों की नहीं। क्या आप जानते हैं इसके पीछे का कारण । अगर आप सोच रहे होंगे कि कार ही नहीं बस की भी तो स्पीड अधिक होती है। इसके बावजूद भी बस की विंडशील्ड तिरछी क्यों नहीं होती है, चलिए आपको इसके पीछे के कारण से रूबरू कराते हैं।

दरअसल बस के मुकाबले कारों की aerodynamic काफी अधिक होती है। आपको आसान शब्दों में बताएं तो तिरछी विंडशील्ड होने की वजह से यह हवा को बहुत ही आसानी से पास करने में अधिक सक्षम होती है। इसके कारण कार की स्पीड में कोई परेशानी नहीं आती है। इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि इस पर कम दबाव हो और यह सुचारू रूप से चलने के बाद ये अधिक माइलेज दे सके। हालांकि बस को बनाते समय एयरोडायनेमिक्स के ऊपर अधिक ध्यान नहीं रखा जाता है।

आपको बता दे आमतौर पर गाड़ियों में दो तरह के विंडशील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। बस और कार के आगे लगे शीशे तिरछे और फ्लैट हो सकते हैं। लेकिन उनकी क्वालिटी में कमी आने पर कई बार ड्राइवर को गाड़ी चलाने में परेशानी हो सकती है। ये धूल वगैरा को रोकने में काम आता है। इसको साफ रखना काफी जरुरी होता है। खासकर सर्दी के समय में इसे वाइपर से साफ करें। आमतौर पर विंडशील्ड लैमिनेटेड और टेम्पर्ड दो तरह के होते हैं।

दोनों विंडशील्ड में क्या अंतर होता है टेम्पर्ड के मुकाबले लैमिनेटेड विंडशील्ड को अधिक बेहतर माना जाता है। इसे बनाने के लिए दो शीशे का इस्तेमाल किया जाता है। बीच में प्लास्टिक होने के कारण दुर्घटना होने पर यह टूट कर बिखरते नहीं हैं। वहीं जो साधारण शीशे होते हैं वो टूट कर बिखर जाते हैं। दूसरी तरफ लैमिनेटेड को टूटने पर आप रिपेयरिंग भी करवा सकते हैं।

संपादक की कलम से

भारत 'हिंदू राष्ट्र' नहीं

'बागेश्वर धाम' के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आजकल एक महायज्ञ कर रहे हैं। महायज्ञ में अनेक साधु-संत मंत्रोच्चारण कर हवन-कुंड में आहुति डाल रहे हैं। बागेश्वर बाबा अपने दरबार में नारे लगवा रहे हैं कि भारत 'हिंदू राष्ट्र' बनकर रहेगा। उनके आह्वान पर उपस्थित भीड़ 'हिंदू राष्ट्र' पर अपनी सहमति देती है। बाबा ने यह भी खुलासा किया है कि संसद में 'हिंदू राष्ट्र' पर जल्द ही कुछ होने वाला है। जहां तक हमारी सूचना है, सरकार की कार्य-सूची में ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। वैसे भी 13 मार्च तक संसद अवकाश पर है। उसके बाद बजट के शेष सत्र के दौरान यह स्पष्ट हो जाएगा कि 'हिंदू राष्ट्र' पर क्या होने वाला है? हमारा मानना है कि भोली और धर्मांध जनता को बरगलाया और उकसाया जा रहा है। यह परोक्ष रूप से एक चुनावी एजेंडा भी साबित हो सकता है। बहरहाल साधु-संतों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी प्रतीकात्मक 'धर्म संसद' का आयोजन किया था, ताकि 'हिंदू राष्ट्र' के मुद्दे को और गरमाया जा सके। आश्चर्य तब हुआ, जब उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि भारत को 'हिंदू राष्ट्र' बनाने से परहेज नहीं होना चाहिए। वह मानते हैं कि भारत अपनी आत्मा और संस्कृति से 'हिंदू राष्ट्र' ही है।

आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत विभिन्न मुद्दों के संदर्भ में मानते रहे हैं कि जिसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ है और इसी देश का नागरिक है, उसकी धार्मिक पूजा-पद्धति कुछ भी हो, वे मूलतः 'हिंदू' ही हैं। संघ प्रमुख मुसलमानों को भी 'हिंदू' मानते रहे हैं, जबकि मुस्लिम नेता, मुल्ला-मौलवी और औसत मुसलमान को भी ऐसी हिंदू-अवधारणा पर सख्त ऐतराज है। दरअसल भारत संवैधानिक तौर पर 'हिंदू राष्ट्र' बन ही नहीं सकता, बेशक यहां की 83 फीसदी से अधिक आबादी हिंदू है अथवा हिंदुओं के साथ अपना सहज और स्वाभाविक धर्म महसूस करती रही है। दूसरे, संविधान के अनुच्छेदों 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की स्पष्ट व्याख्या है। यानी कोई भी नागरिक किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। एक निश्चित पूजा-पद्धति में आस्था रख सकता है। अपने आध्यात्मिक मूल्यों का प्रचार-प्रसार कर सकता है। बेशक बाद में जोड़ी गई, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में ही स्पष्ट है कि भारत एक 'पंथनिरपेक्ष' देश है। हालांकि संविधान के मूल ग्रंथ में श्रीराम के दरबार का चित्र है। राजा विक्रमादित्य के दरबार, बौद्ध सम्राट अशोक, अर्जुन को श्रीकृष्ण का गीता-उपदेश, महाभारत, भगवान महावीर स्वामी, भगीरथ और गंगा-अवतरण, छत्रपति शिवाजी, महाबलीपुरम मंदिर और महात्मा गांधी की 'दांडी यात्रा' आदि की तस्वीरें भी प्रकाशित की गई हैं। मुगल बादशाहों में अकबर की तस्वीर ही दिखाई देती है।

ज्यादातर तस्वीरें सनातन धर्म और उसकी घटनाओं से जुड़ी हैं। महाराजाओं और शासकों की भी तस्वीरें ऐसी छापी गई हैं, जो हिंदू धर्म से जुड़े थे अथवा उसमें आस्था रखते थे। वे वैदिक संस्कृति के भी पक्षधर थे, लिहाजा 'वैदिक गुरुकुल' की तस्वीर भी संविधान के ग्रंथ में छापी गई है। प्रथमदृष्ट्या सोच सनातनी ही लगती है। यह ग्रंथ भी प्राचीन नहीं है, 1950 के आसपास छापा गया था। सिर्फ इन्हीं के आधार पर भारत को 'हिंदू राष्ट्र' घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश संविधान और संसद से चलता है। यदि फिर भी 'हिंदू राष्ट्र' बनाने की कोई कोशिश की जाती है, तो वह भयंकर विघटनकारी होगी। बेशक संसद के दोनों सदनों में भाजपा और उसके समर्थक दलों का पर्याप्त बहुमत है, लेकिन ऐसे मुद्दे बहुमत से तय नहीं किए जा सकते।

योगेंद्र योगी

भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस और अन्य दलों की तीखी आलोचना करती आई है। इस आलोचना का तात्पर्य यह नहीं है कि भाजपा भी इन्हीं दलों की तरह आचरण करने लगे और दलील यह दे कि ऐसा तो उनके शासन में भी होता रहा है, इसलिए इसमें गलत क्या है।

जस्टिस गवर्नर व अदालत की गरिमा

भाजपा और आंध्र सरकार के बीच कई बार टकराहट हो चुकी है। यदि राजनीतिक धरना-प्रदर्शन के हालात बनते हैं तो वह सिर्फ राज्यपाल के खिलाफ ही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज के खिलाफ भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जज रहने के कारण राज्यपाल को विवादों में घसीटा जाएगा। राजनीति में चूंकि आरोप-प्रत्यारोपों की कोई सीमा नहीं है, इसलिए विवाद किसी भी हद तक जाने पर इसकी चपेट में सेवानिवृत्ति के बाद राज्यपाल बने जज भी आएंगे। राज्यपाल से सरकार और विधानसभा से होने वाली टकराहट के कई मामले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। जज के राज्यपाल बनने पर यदि ऐसी नौबत आती है, तो अदालतों को अजीबोगरीब हालात का सामना करना पड़ेगा'

भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस और अन्य दलों की तीखी आलोचना करती आई है। इस आलोचना का तात्पर्य यह नहीं है कि भाजपा भी इन्हीं दलों की तरह आचरण करने लगे और दलील यह दे कि ऐसा तो उनके शासन में भी होता रहा है, इसलिए इसमें गलत क्या है। भाजपा की केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अब्दुल नजीर को आंध्रप्रदेश का राज्यपाल नियुक्त करने के मामले में ऐसी ही दलील दे रही है। भाजपा यह कहते हुए नजीर की नियुक्ति को जायज ठहरा रही है कि ऐसा तो कांग्रेस के शासन में भी होता रहा है। भाजपा यह भूल गई कि कांग्रेस ऐसे कारनामों के कारण सत्ता से बाहर है। भाजपा अपनी सुविधा से यह नहीं कर सकती कि जिसमें उसे नुकसान नजर आए उसमें कांग्रेस को कोसे और जहां छिपा हुआ एजेंडा लागू करना हो, वहां कांग्रेस का उदाहरण पेश कर दे। इस नकारात्मक उदाहरण से निश्चित तौर पर भाजपा और न्यायाधीशों की छवि पर उंगलियां उठेंगी। न्यायाधीश नजीर का गलत उदाहरण पेश करके भाजपा अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। सवाल यह नहीं है कि नजीर ने सुप्रीम कोर्ट में जज रहते हुए अयोध्या और तीन तलाक के मुद्दे पर केंद्र सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। बड़ा सवाल न्यायपालिका की नैतिकता और शुचिता का है जिसे बनाए रखने की मौजूदा दौर में कम से कम किसी राजनीतिक दल से तो अपेक्षा नहीं की जा सकती। नजीर को राज्यपाल बनाए जाना एक तरह से सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायाधीशों के पुनर्वास का रास्ता देना है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स के ऐसे जज जिन्होंने सरकारों के पक्ष में फैसला दिया होगा, वे सत्ताधारी दलों के कृपापात्र होंगे। जब भी सही मौका मिलेगा सरकार उनका पुनर्वास करके उन्हें अनुग्रहित कर देगी। यह परिपाटी न सिर्फ न्यायपालिका बल्कि देश की न्याय व्यवस्था के भी अनुकूल नहीं है। किसी लालच या आकर्षण के बूते दिए गए फैसलों में यह पता लगाना आसान नहीं होगा कि इसमें सच्चाई कितनी है। यही माना जाएगा कि सरकार का साथ देने के फैसलों के एवज में किसी प्रशासनिक या संवैधानिक पद पर नियुक्त करके न्यायाधीश को उपकृत किया गया है। राजनीतिक दलों के नेताओं के दामन तो दागदार होते रहे हैं, किन्तु यह बुराई यदि न्यायपालिका तक पहुंच गई तो न्याय पर आम लोगों का विश्वास कायम रखना मुश्किल हो जाएगा। सेवानिवृत्त होकर किसी पद को लेने पर न्यायाधीश के कार्यकाल के दौरान दिए गए फैसलों पर सवाल उठेंगे, जैसे कि जज नजीर की नियुक्ति को लेकर उठ रहे हैं। देश में पहले ही न्याय पाने वालों की लंबी कतार लगी हुई है। न्याय पाने के लिए होने वाला खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यायपालिका जजों की कमी से जूझ रही है। जटिल न्यायिक प्रक्रिया से लोगों की हताशा बढ़ रही है। ऊपर से यदि यह प्रवृत्ति न्यायाधीशों की घर कर गई कि सेवानिवृत्ति के बाद सरकार उनका भला कर देगी, तो न्यायिक फैसलों से आम लोगों का न्यायपालिका पर बचा हुआ विश्वास भी दरकने लगेगा।

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की ताजपोशी से इस बात को बल मिलता है कि केंद्र सरकार किसी न किसी रूप में न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार के राज्यपाल के पद को भरने के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हो, किन्तु न्यायाधीशों को इसमें शामिल करने से न्यायपालिका और सरकार की साख पर सवाल उठना लाजिमी है। केंद्र सरकार वैसे ही जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से टकराव के मुहाने पर खड़ी है। सरकार ने कॉलेजियम के जरिए होने वाली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति से इंकार कर दिया है। उधर सुप्रीम कोर्ट नियुक्ति के मसले पर सरकार द्वारा बनाए गए कानून को अमान्य घोषित कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि ऐसा करके सरकार न्यायपालिका में दखलअंदाजी करने का प्रयास कर रही है। भाजपा की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के चहेतों की नियुक्ति की जाती है, वहीं न्यायविदों का कहना है कि सरकार अपने कृपापात्रों को नियुक्त कराने के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को मानने से इंकार कर रही है। एक तरफ केंद्र सरकार अपनी पसंद के जजों की नियुक्ति कराने पर आमदा है, वहीं दूसरी तरफ सेवानिवृत्त जजों को मलाईदार पोस्ट देकर न्यायाधीशों को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। राज्यपाल पद कहने को संवैधानिक होता है, किन्तु यथार्थ में राज्यपाल के राजनीतिक विवादों में घिरे रहने के कई उदाहरण मौजूद हैं। गैर-भाजपा शासित राज्यों में राज्यपाल और राज्य सरकार में टकराव की घटनाएं होती रहती हैं। उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़ इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। धनखड़ जब तक पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल रहे, तब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनका टकराव बना रहा। तमिलनाडु सहित कई राज्यों में राज्यपालों के खिलाफ राजनीतिक धरना-प्रदर्शन तक हुए हैं। राज्यपालों पर भ्रष्टाचार सहित मनमानी करने के कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे नजीर के आंध्रप्रदेश का राज्यपाल बनने पर ऐसी नौबत नहीं आएगी। वैसे भी आंध्रप्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है।

भाजपा और आंध्र सरकार के बीच कई बार टकराहट हो चुकी है। यदि राजनीतिक धरना-प्रदर्शन के हालात बनते हैं तो वह सिर्फ राज्यपाल के खिलाफ ही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज के खिलाफ भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जज रहने के कारण राज्यपाल को विवादों में घसीटा जाएगा। राजनीति में चूंकि आरोप-प्रत्यारोपों की कोई सीमा नहीं है, इसलिए विवाद किसी भी हद तक जाने पर इसकी चपेट में सेवानिवृत्ति के बाद राज्यपाल बने जज भी आएंगे। राज्यपाल से सरकार और विधानसभा से होने वाली टकराहट के कई मामले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। जज के राज्यपाल बनने पर यदि ऐसी नौबत आती है, तो अदालतों को अजीबोगरीब हालात का सामना करना पड़ेगा। अदालतों को ऐसे मामलों की सुनवाई करनी पड़ेगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जज शामिल रहा हो। यदि अदालत ने राज्यपाल के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी कर दी तो परोक्ष तौर पर न्यायपालिका पर भी होगी, क्योंकि राज्यपाल पूर्व में जज रह चुके हैं। विवाद की ऐसी स्थितियों से बेशक राजनीतिक दलों के स्वार्थ सधते हों, किन्तु इससे न्यायपालिका के प्रति जनभावना में बनी आस्था खंडित हुए बगैर नहीं रहेगी। सरकारों की स्वार्थसिद्धी की इस तरह की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने का एकमात्र तरीका यही है कि सुप्रीम कोर्ट पहल करते हुए लक्ष्मण रेखा तय कर दे, अन्यथा इस गिरावट के छींटे अदालतों पर पड़े बगैर नहीं रहेंगे।

19 फरवरी की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को हत्या की गई थी और उनकी मृत्यु के 13वें दिन 19 फरवरी 1948 को उनकी अस्थियों को देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग पवित्र सरोवरों में विसर्जित कर दिया गया। एक कलश को इलाहाबाद में गंगा नदी में प्रवाहित किया गया। इस मौके पर दस लाख से अधिक लोगों ने नम आंखों से साबरमती के इस संत को अंतिम विदाई दी।

1742 : महान मराठा दिग्गज नाना फडनवीस का जन्म।

वैलेंटाइन स्पेशल- 14 फरवरी तक लाइव- इसे खास बनाने के लिए वन स्टॉप शॉप |

1809 : ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का जन्म।

1809 : अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का जन्म।

1818 : चिली ने स्पेन से आजादी की औपचारिक घोषणा की।

1922 : महात्मा गांधी ने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति को असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के लिए राजी किया।

1928 : गांधी जी ने बारदोली में सत्याग्रह के संकेत दिए।

1948 : महात्मा गांधी की अस्थियों को इलाहाबाद में गंगा नदी सहित विभिन्न पवित्र स्थलों पर विसर्जित किया गया।

1975 : भारत को चेचक से मुक्त देश घोषित किया गया।

1994 : चोरों ने नार्वे के महान चित्रकार एडवर्ड मंक की विश्वप्रसिद्ध रचना 'द स्क्रीम' को चुरा लिया। हालांकि बाद में इस कृति को बरामद कर लिया गया।

1996 : फ़िलिस्तीनी मुक्ति संगठन के नेता यासर अराफात को गाजा में फ़िलिस्तीन के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई।

2002 : ईरान के एक विमान के ख़ुर्रमबाद हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 119 लोगों की मौत हुई।

2002 : पाकिस्तान के अधिकारियों ने अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल के अपहरण के संदेह में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी अहमद उमर शेख को गिरफ्तार किया।

2009 : भारत के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला भैंस क्लोन विकसित किया। यह भारतीय वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि थी।

मरने के बाद जीना

विदेशियों की सोच, उनके कारनामे, नए विषयों पर सर्वे, हमेशा सोचने को उद्वेलित करते हैं। दिलचस्प यह है कि हम उनसे काफी कुछ सीखने की खासी ईमानदार कोशिश करते हैं। वो बात अलग है कि राग हम अपनी पारंपरिक भारतीय संस्कृति का अलापते रहें। हमने इतना कुछ विदेशी खाना पीना, हवा पानी हजम कर लिया। विदेशी वस्त्र आत्मसात कर लिए जिन्हें भुलाना और छोडना अब मुश्किल है। कम कपड़े उतार कर फेंकना सभ्य होना नहीं। एक बार छोटे छोटे रंग बिरंगे कपड़े पहनने का शौक हो जाए तो ज़्यादा कपड़े पहनना परेशान करने लगता है। बात कपड़ों से, मरने के बाद जीने, पर लाते हैं। अब बता रहे हैं कि विदेश में मृत शरीर को फ्रिज करवाने का ट्रेंड उग रहा है। अमेरिकाजी और रूसजी में सैंकड़ों लोग ऐसा कर चुके हैं। ज़िंदगी से प्यार करने वाले ये लोग अपने नश्वर शरीर की ममी नहीं बनवा रहे बल्कि फिर से ज़िंदा हो जाने की हसरत पाल कर अपने मृत शरीर को फ्रिज करवा रहे हैं। कमबख्त जीने की तमन्ना होती ही ऐसी है। जीने की तमन्ना पहले होती है और मरने का इरादा बाद में रहता है। गाइड करने वाले, हमारे तो गाने भी ऐसा कहते हैं। हमारे यहां एक दूसरे को मारकर, प्रिय शरीर के लगभग तीन दर्जन टुकड़े कर, नए फ्रिज में रखने का, फिर अशुभ मुहूर्त निकालकर, उचित समय पर जंगल या मनचाही जगहों पर उन टुकड़ों को फेंकने का बिल्कुल ताज़ा ट्रेंड जीवित हो उठा है। इस सन्दर्भ में हम विदेशियों से आगे निकल आए हैं। मरने के बाद जीने की नवोन्मेषी सोच के मामले में विदेशी वैज्ञानिक हमसे आगे हैं। वे मान रहे हैं कि मृत लोग अभी होश में नहीं, बेहोश हुए हैं। वैज्ञानिक अमुक तकनीक के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, शायद वह आशीर्वाद दे दे और मृत शरीर फिर से जीवित शरीर हो जाएं। फ्रिज से निकलकर फिर से ज़िंदगी की इच्छाओं की स्वादिष्ट आइसक्रीम खाने लगें।

हमारे यहां तो जिंदा रहना भी मुश्किल होता जा रहा है और मरना भी आरामदायक नहीं रहा। इच्छा मृत्यु चाहने वाले बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उन्हें अनुमति देने वालों की इच्छा नहीं बढ़ रही। वे चाहते हैं कि बीमार, असहाय व गरीब अस्पतालों में भर्ती, रिश्तेदारों व परिवारों वालों को परेशान कर देने वाले लोग, यूं ही मौत की गोद में फ्रीज होते रहें। जीते हुए मरते रहें, एक दिन में कई बार मरें। बताते हैं मरने के बाद जीवित कर देने का प्रयोग करने में लगे व्यावसायिक लोग कई देशों में प्रयोगशालाएं स्थापित कर रहे हैं। विदेशी वैज्ञानिकों को चाहिए कि आलतू फालतू काम छोडक़र भूख न लगने की गोली बनाएं, प्यार बढ़ाने का पाउडर बनाएं, नफरत के टुकड़े करने के स्प्रे का आविष्कार करें। प्रकृति और विज्ञान की उचित मित्रता ही सही विकास कर सकती है। लेकिन जब इस समन्वय के सूत्रधार ही पूरी तरह से कुदरती नियमों, विशेषकर इंसानी ज़िंदगी के नैसर्गिक प्रारूप को विकृत करने में संलिप्त हों तो लगता है सृष्टि के सर्वनाश का रास्ता और चौड़ा कर दिया है। कृत्रिम बुद्धि भी इंसानी दिमाग पर राज करने लगी है। इंसानी बुद्धि कुबुद्धि में तब्दील होती जा रही है। जो आया उसे एक दिन जाना है, इस विचार के विरुद्ध चलना सद्बुद्धि का उदाहरण हो गया है।

प्रभात कुमार

धुंध भरे इंतजार का एहसास

कल तक जो आपके घर में दूध में पानी मिला कर बेचते थे, उन्हें अगर आज मिलावट के विरुद्ध और कुपोषण के खिलाफ जंग छेड़ते देखते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपके इलाके में जल संकट गहरा हो गया है, और आपके दूध वाले भय्या जो पहले आपको पानी में दूध मिला कर बेचते थे, अब दूध में भी पानी नहीं मिला पाते। दूध को गाढ़ा करने वाले पाऊडर के दाम बढ़ गये हैं, इसलिए उनके मन में बिना मिलावट दूध बेचने का पुण्य कमाने का जज्बा पैदा हो गया है। आज शायद 'हींग लगे न फिटकड़ी, रंग भी चोखा आए' का नया चलन पैदा हो गया है। अब दूध में पानी मिलाने का झंझट काहे पालना, जबकि इसके विरुद्ध विशुद्ध संस्कृति का नारा लगाने से ही आपकी नेतागिरी की पालकी को किराये के कहार उठा लेते हैं। दाम चुकाओं तो आज क्या नहीं मिल जाता। पहले किराये पर रैलियां सजती थीं, भीड़ जुटती थी, मंच सजते थे, मतदान बूथों के बाहर जाति और धर्म के नाम पर बिके वोटरों की कतारें सजती थी, अब तो बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया में सेंध लग जाती है। आपका व्हाट्सएप बिकने लगा। मोहल्ले में वोट मांगते नेता अब अपने जूते क्यों चटखायें, आपकी चिरौरी करते नजऱ क्यों आएं? व्हाट्सएप से आपके मन और रुझान की खाना तलाशी करते हुए मनभावन घोषणाओं से अपने वोटरों का मन जीत लें, और राजनीति में वंशवादी परम्पराओं को स्थापित कर लें। बंधु, ज़माना बदल गया है। नई सदी ने नई समझ दे दी है। अब सदियों से पिछड़े हुए इस देश की गुरुतर आबादी को हर समस्या का हल वृहत परिप्रेक्ष्य में करना सीखना होगा। अब समझ की व्याकरण ही न बदलो, अपने नये शब्द कोषों में शब्दों के अर्थ भी बदल डालो। वर्तमान से असंतुष्ट लोगों को अतीत की गरिमा से सराबोर कर दो। आंकड़े बताते हैं कि मिलावटी दूध के कुपथ्य ने पांच साल की उम्र के आधे से अधिक और बारह साल की उम्र तक आधे से कम नौनिहाल मौत के या अपहरण के हवाले कर दिये, तो लोगों को वर्तमान के प्रति असंतोष की ज्वाला में दहकने न दो। बल्कि उन्हें बताओ कि हमारे यहां तो शुद्ध पवित्र वातावरण में कामधेनु गायों के मिल जाने की परम्परा है। इस देश में उसी परम्परा को जीवित करने का महती प्रयास हो रहा है।

तब आम के आम और गुठलियों के दाम मिलेंगे। लेकिन बंधुवर, हथेलियों पर सरसों तो नहीं जमायी जा सकती न। देश में अतीत का वैभव लौटाने के लिए इंतजार करना ही होगा। इस देश में कामधेनु और कल्पवृक्ष का युग भी लौट कर आएगा। तब यह जीवन, समाज और गलत भौतिकवादी मूल्यों का गंदलापन छंट जाएगा। इन दिनों का इंतजार करो, तब तुम्हें नहीं कहना पड़ेगा कि 'हर शाख पर उल्लू बैठे हैं, इस चमन का यारो क्या होगा?' फिलहाल इस उजड़ते चमन की सूखी डालियों पर महंगाई, भ्रष्टाचार, नौकरशाही और गाल बजाते मसीहाओं के उलूकनुमा व्यवहार को सहन करो क्योंकि कल तो इन्हीं डालियों पर सोने की चिडिया चहचहाएंगी। देश में सतयुग की वापसी चाहते हो न, तो आज के इस कलयुग और अंधेरनगरी चौपट राजा के माहौल को सहन करो। बड़े बूढ़ों ने भी कहा तो है कि सहज पके सो मीठा होय। इस काल में अगर राम राज्य की वापसी चाहते हो, तो आज इस दानव राज को असाध्य बीमारी की तरह स्वीकार करो। देखो, उच्छृंखलता की निशानी है, यह विशुद्ध संस्कारित समाज की परिभाषा में नहीं आता। बड़े बूढ़े बोले। हमें इन परिभाषाओं को बदलना नहीं है, इनमें संयम, धीरज और अनुशासन के नये अर्थों को स्थापित करना है। फरमाया। उन्हें समझाने की कोशिश कीजिये कि आयातित मूल्यों ने हमारी संस्कृति को इतना गंदला कर दिया है कि अब उसकी विरूपता पहचानी भी नहीं जाती।

सुरेश सेठ

एमएसएमई उन्नयन के लिए रैम्प योजना

वहां से इसे पुनः अन्तिम अनुमोदन हेतु ''समग्र निगरानी और नीति अवलोकन'' करने वाली ''शीर्ष राष्ट्रीय एमएसएमई परिषद'' को भेजा जाएगा। वहीं से यह निर्धारित होगा कि इस ''रणनीतिक प्लान'' में जो संस्तुतियां दी गई हैं, वे कितनी व्यावहारिक व सार्थक हैं। इसी आधार पर ''विस्तृत पैकेज'' हिमाचल को एमएसएमई के सशक्तीकरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। हमारे प्रदेश का यह अति महत्वपूर्ण औद्योगिक सांझीदार आशान्वित है कि हितधारकों से विचार-विमर्श के पश्चात गहन मंथन से एक सशक्त ''प्रारम्भिक प्लान'' बनेगा, जिससे हमारे प्रदेश का एमएसएमई सैक्टर और मज़बूत बनकर उभरेगा और इस पहाड़ी प्रदेश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगा'

140 करोड़ की आबादी वाले भारत में 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम' की भूमिका देश की आर्थिकी व रोजग़ार सृजन में अहम है। देश का 48 प्रतिशत से अधिक निर्यात इनके द्वारा होता है व राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद में इस सैक्टर का योगदान 30 प्रतिशत से भी अधिक का है तथा 11 करोड़ से अधिक रोजग़ार सृजित करने वाला यही सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो कहीं न कहीं गांधी के ''ग्रामोद्योग उत्थान'' की परिकल्पना के साथ भी तादात्म्य स्थापित करता है। यह क्षेत्र बड़े उद्यमों के सहायक उद्योगों के रूप में भी ''पूरक'' की भूमिका निभाता है। वैसे तो आज़ादी के बाद गरीबी का प्रतिशत देश में शनैः-शनैः कम हुआ है, परन्तु इस कम होती दर को 'कोविड-19' के विस्फोट ने मानो 'रिवर्स ब्रेक' लगा दी। 2011 के मुकाबले 2019 में अति दरिद्रता की दर भारत में 12.3 प्रतिशत प्वांइट कम रही, परन्तु 2020 में इस महामारी के बाद गरीबी दर पुनः वर्ष 2016 के स्तर पर पहुंच गई। सबसे अधिक क्षति इस 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम' क्षेत्र को पहुंची। तालाबंदी से औद्योगिक उत्पादन रुक गया, लाखों लोग बेरोजग़ार हो गए, उद्योगों की देनदारियां बढ़ गई। उद्योग जगत के लिए ये न उभर पाने वाला धक्का था। 'कल्याणकारी राज्य' होने के नाते सरकार ने इस क्षेत्र को उबारने के लिए ''आत्मनिर्भर भारत'' अभियान के अन्तर्गत कई कदम उठाये, जिनमें ''एमरजैन्सी क्रेडिट लोन गारन्टी योजना'' व ''फंड ऑफ फंड्स'' प्रमुख थीं, जिनका मुख्य उद्देश्य एमएसएमई को उस समय अति आवश्यक तरलता (लिक्विडिटी) प्रदान करना था ताकि वे अपनी आवश्यक देनदारियों से शीघ्र निपट सकें। बड़े उद्यमों के मुकाबले 'एमएसएमई' सैक्टर कुछ मूलभूत समस्याओं से प्रायः दो-चार होता रहता है।

मसलनः- भौतिक बुनियादी ढांचागत बाधाएं, बहुत से असंगठित उद्यमों का मुख्य धारा (ऑरगेनाइज्ड सैक्टर) में शामिल न हो पाना, उत्पादन में आधुनिक प्रौद्योगिकी व तकनीक की कमी, क्षमता निर्माण की समस्या, ऋण व जोखिम पूंजी (वैंचर कैपिटल) तक सहज पहुंच न होना, उद्यम स्थापना से पूर्व सरकारी अनुमतियों में समय लगने से परियोजना क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी, विलंबित भुगतान की समस्या आदि। जर्मनी, चीन जैसे देशों में एमएसएमई का उनकी अर्थव्यवस्था में क्रमशः लगभग 55 प्रतिशत और 60 प्रतिशत का योगदान है, जो इस बात का संकेत करती है कि हमारे देश के इस क्षेत्र को अभी एक लंबी यात्रा तय करनी है। गत वर्ष एमएसएमई मंत्रालय ने कोविड उपरान्त इस सेक्टर के सर्वांगीण विकास व पुनरुत्थान हेतु ''विश्व बैंक'' से मन्त्रणा की व कई बैठकों के फलस्वरूप व यूके सिन्हा समिति, केवी कामथ समिति तथा प्रधानमंत्री की ''आर्थिक सलाहाकार परिषद'' की सिफारिश पर विश्व बैंक पोशित ''रैम्प'' (रेजिग़ एण्ड एकसीलरेटिंग एमएसएमई परफॉरमैंस) योजना को स्वीकृति मिली। इसका मुख्य उद्देश्य इन उद्यमों की बाज़ार और बैंक ऋण तक पहुंच में सुधार करना, केन्द्र एवं राज्यों में स्थित विभिन्न संस्थानों और तन्त्र को सुदृढ़ करना, तकनीक के विश्व स्तरीय मानकों पर आधारित उत्पाद तैयार करना, विलंबित भुगतान का निराकरण करना, पर्यावरण अनुकूल (ग्रीन तकनीक) उत्पाद तैयार करना आदि है। यह 5 वर्ष की (2022 से 2027 तक) योजना है। ''रैम्प'' का महत्वपूर्ण घटक ''रणनीतिक निवेश योजना'' (स्ट्रैटेजिक इन्वैस्टमेंट प्लान) तैयार करना है। हिमाचल सरकार ने भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए केन्द्र को आवेदन किया था, क्योंकि प्रदेश में स्थापित उद्यमों में लगभग 99 प्रतिशत उद्यम ''सूक्ष्म, लघु व मध्यम'' की श्रेणी में आते हैं।

भारत सरकार द्वारा अभी तक 21 राज्यों को इस योजना में शामिल किया गया है, जिसमें हिमाचल भी शामिल है व प्रारम्भिक 5 करोड़ रुपए का अनुदान ''रणनीतिक निवेश योजना'' तैयार करने के लिए स्वीकृत किया गया है। लगभग 29000 एमएसएमई उद्यम अभी तक ''उद्योग विभाग'' के साथ पंजीकृत हैं। हो सकता है और भी कई असंगठित क्षेत्र के ऐसे उद्यम होंगे जो एमएसएमई ''परिभाषा'' के दायरे में आते हों, पर समुचित जानकारी के अभाव में अभी तक छूट गए हों। एक अनुभवी, प्रसिद्ध व मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा प्रदेश में इस महत्वपूर्ण सैक्टर का विस्तृत सर्वेक्षण/विश्लेषण करवाया जाएगा। क्या प्रमुख अंतराल और बाधाएं हैं, जो इस क्षेत्र के विकास में बाधक बन रही हैं, इस पर समग्र दृष्टि से हर बिन्दु का आकलन इस प्लान में किया जाएगा। मार्च 2023 से इस योजना पर कार्य शुरू होने की संभावना है व लगभग 6 माह की अवधि में ''प्रारम्भिक प्लान'' उद्योग विभाग द्वारा तैयार कर प्रधान सचिव उद्योग की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष कमेटी को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। वहां से इसे पुनः अन्तिम अनुमोदन हेतु ''समग्र निगरानी और नीति अवलोकन'' करने वाली ''शीर्ष राष्ट्रीय एमएसएमई परिषद'' को भेजा जायेगा। वहीं से यह निर्धारित होगा कि इस ''रणनीतिक प्लान'' में जो सन्स्तुतियां दी गई हैं, वे कितनी व्यावहारिक व सार्थक हैं।

ब्रीफ न्यूज

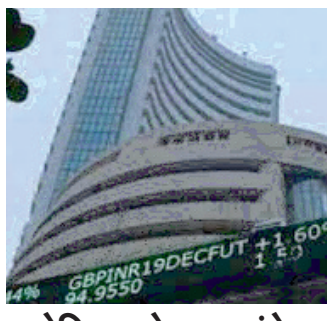

अमेरिका से एक संकेत और निवेशकों ने कमा लिए 3 लाख करोड़, जानिए क्यों बाजार में आई जबरदस्त तेजी

भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी आई है। सेंसेक्स करीब 900 अंक चढ़ गया। वहीं, निफ्टी 18,100 के पार बंद हुआ। अमेरिका में ब्याज दर वृद्धि के मोर्चे पर नरमी के संकेत के बाद बाजार में यह तेजी दर्ज हुई है। अधिकतर सेक्टोरियल सूचकांक हरे निशान पर बंद हुए।

नई दिल्ली : शेयर बाजार में निवेशकों ने खूब चांदी कूटी। भारतीय शेयर बाजार भारी बढ़त के साथ बंद हुआ है। निफ्टी 1.35 फीसदी या 241 अंक बढ़कर 18,101 पर बंद हुआ। वहीं, सेंसेक्स 1.41 फीसदी या 846 अंक चढ़कर 60,747 पर बंद हुआ। बीएसई पर करीब 1986 शेयर बढ़त के साथ, 1542 शेयर गिरावट के साथ और 155 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए। सेक्टर्स की बात करें, तो आईटी, पावर, ऑटो, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, मेटल और पीएसयू बैंक इंडेक्स में 1-2 फीसदी की बढ़त रही। बीएसई मिडकैप इंडेक्स करीब 1 फीसदी ऊपर रहा। वहीं, स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.5 फीसदी की तेजी रही।

ब्याज दर के मोर्चे पर नरमी की उम्मीद

बाजार को उम्मीद है कि महंगाई नीचे आ रही है और फेड ब्याज दर (Fed Interest Rate) वृद्धि के मामले में नरम पड़ सकता है। अमेरिका के प्रमुख संकेतकों ने फेड द्वारा ब्याज दरों में इजाफे के मोर्चे पर नरमी के संकेत दिए हैं। भारतीय बाजार में आज की तेजी ब्याज दर वृद्धि की चिंताओं में कमी आने के चलते ही है। हालांकि, विश्लेषकों का कहना है कि उतार-चढ़ाव बना रहेगा। क्योंकि यह देखना बाकी है कि अर्थव्यवस्था मंदी से बच सकती है या नहीं। इस समय निवेशकों का फोकस कंपनियों के दिसंबर तिमाही के नतीजों पर भी है। सोमवार शाम आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीसीएस (TCS) के नतीजे आने हैं।

निवेशकों ने कमाए 3 लाख करोड़

दलाल स्ट्रीट में आज की तेजी में निवेशकों ने तीन लाख करोड़ रुपये कमाए हैं। सोमवार को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल बाजार पूंजीकरण 282.79 लाख करोड़ रुपये हो गया। एक्सपर्ट्स के अनुसार, शुक्रवार को जारी हुआ यूएस इकनॉमिक डाटा ग्लोबल मार्केट के नजरिए से महत्वपूर्ण है। सभी आंकड़े यूएस इकनॉमी में खतरे के संकेत नहीं दे रहे हैं।

इन शेयरों में रही तेजी

इससे पहले बाजार में पिछले तीन दिनों से गिरावट देखने को मिल रही थी। आज सेंसेक्स के शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इंडसइंड बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एक्सिस बैंक प्रमुख रूप से लाभ में रहे। आईटी कंपनियों के शेयरों में अच्छी मांग देखने को मिली। केवल तीन शेयर शेयर टाइटन, बजाज फिनसर्व और मारुति नुकसान में रहे। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने शुक्रवार को 2,902.46 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे।

वैश्विक बाजारों का हाल

एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग लाभ में रहे। यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरुआती कारोबार में तेजी का रुख था। अमेरिकी बाजार शुक्रवार को बढ़त में रहे थे।

आईटी सेक्टर के लिए उम्मीद बंधी

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, 'अमेरिका में वेतन वृद्धि की गति धीमी पड़ने और सेवा गतिविधियों में गिरावट के साथ महंगाई के नरम होने से ऐसी संभावना जतायी जा रही है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक नीतिगत दर के मामले में अपेक्षाकृत कम आक्रामक रुख अपनाएगा।

इन उत्पादों पर घटा जीएसटी, पेंसिल-शार्पनर और राब हुए सस्ते, पान मसाले पर भी बड़ा फैसला

एनटीवी न्यूज

जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक दिल्ली में आयोजित हुई है। इस बैठक में कई उत्पादों पर जीएसटी घटाने का फैसला लिया गया है। लिक्विड जैगरी पर जीएसटी को 18 से घटाकर जीरो कर दिया गया है। इसके अलावा पेंसिल और शार्पनर पर भी जीएसटी घटाया गया है।

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की दो रिपोर्ट्स को काउंसिल द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। 49 वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक (49th GST Council Meeting) के बाद प्रेस ब्रीफिंग में वित्त मंत्री ने यह बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि 16,982 करोड़ रुपये का सारा जीएसटी मुआवजा सैस क्लियर किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आज सारा बकाया जीएसटी कंपनसेशन सैस जारी कर दिया गया है। 49 वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राज्यों के वित्त मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में राज्यों ने वित्त वर्ष 2021-22 के जीएसटी मुआवजे की गलत गणना का मुद्दा उठाया था। इस बैठक से पहले सीतारमण ने कहा था कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाने के लिए राज्यों को एक एग्रीमेंट पर पहुंचने की जरूरत है।

राब और पेंसिल-शार्पनर पर जीएसटी घटा

जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई उत्पादों पर जीएसटी घटाने का फैसला लिया गया है। तरल गुड़ (लिक्विड जैगरी/राब) पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 0 कर दिया गया है। वहीं, अगर यह प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड है, तो 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। इसके अलावा पेंसिल-शार्पनर पर भी जीएसटी को घटाया गया है। पेंसिल और शार्पनर पर जीएसटी रेट को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है।

पान मसाला पर यह हुआ फैसला

जीएसटी काउंसिल की बैठक में पान मसाला और गुटखा पर भी बड़ा फैसला हुआ है। अब पान मसाला और गुटखा पर उत्पादन के हिसाब से जीएसटी लगेगा। इन पर कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन लागू होगा।

मिलेट्स पर अगली बार होगा विचार

वित्त मंत्री ने बताया कि मोटे अनाज यानी मिलेट्स के बारे में जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में विचार किया जाएगा।

भारत के 40 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी बनने में रोड़ा बनेगी तस्करी, सरकार को कर में बड़ा नुकसान

नई दिल्ली। फिक्की की तस्करी एवं जाली वस्तुओं से अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान के खिलाफ समिति (कैस्केड) की एक रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है। तस्करी से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। यह सरकार के अमृतकाल के दृष्टिकोण के तहत भारत के 40 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी बनने की राह में रोड़ा बन सकता है। भारतीय उद्योग महासंघ (फिक्की) की तस्करी एवं जाली वस्तुओं से अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान के खिलाफ समिति (कैस्केड) की एक रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है। इसमें कहा गया है कि पांच उद्योगों में अवैध व्यापार की वजह से भारत सरकार को कर के रूप में होने वाला नुकसान 2019-20 में 163 फीसदी बढ़कर 58,521 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

इन पांच अवैध व्यापार वाले उद्योगों में अल्कोहल, मोबाइल फोन, दैनिक उपयोग वाली घरेलू एवं निजी वस्तुएं, पैकेट बंद खाद्य पदार्थ और तंबाकू उत्पाद शामिल हैं। कर चोरी से होने वाले नुकसान में सबसे ज्यादा 227 फीसदी की वृद्धि अल्कोहल और तंबाकू वाले उत्पादों के अवैध व्यापार से हुई है।

तस्करी 21वीं सदी का अपराध: फिक्की कैस्केड के चेयरमैन अनिल राजपूत ने कहा कि तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत अभियान चलाने की जरूरत है। यह अभियान तस्करी पर लगाम लगाने के लिए उपभोक्ताओं और युवाओं के बीच जागरूकता पैदा करेगा, जो राष्ट्र निर्माण में बाधा बन गया है। उन्होंने कहा, तस्करी को 21वीं सदी का अपराध करार दिया गया है।

हरित विकास अब प्राथमिकता, पर्यटन से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, एआई को बढ़ावा देगा शोध

देश में मोबाइल फोन उत्पादन इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ पुर्जों के आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली लीथियम बैटरियों पर लगने वाले सीमा शुल्क को भी 21 से कम करके 13 फीसदी कर दिया गया है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बजट में विनिर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यटन और पर्यावरण के क्षेत्र में कई सहूलियतों का एलान कर अर्थव्यवस्था को गति देने की योजना बनाई है। हरित विकास अब देश की प्राथमिकता है। पर्यटन में सरकार ने इस बार कई प्रावधान किए हैं। इनसे रोजगार सृजन भी होंगे। वहीं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में शोध के लिए भी नए केंद्र बनाए जाएंगे।

देश में मोबाइल फोन उत्पादन इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ पुर्जों के आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली लीथियम बैटरियों पर लगने वाले सीमा शुल्क को भी 21 से कम करके 13 फीसदी कर दिया गया है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे। पेट्रोल-डीजल की महंगाई से परेशान जनता ई-वाहनों की ओर आकर्षित होगी। पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता घटने से पर्यावरण को भी लाभ होगा।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के लिए देश में तीन उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना का भी एलान किया गया है। देश के शीर्ष शिक्षण संस्थानों में बनाए जाने वाले ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कृषि, स्वास्थ्य, सतत विकास और शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना पर काम करेंगे।

पर्यटन को लेकर मिशन मोड में काम करने की योजना है। पर्यटन क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावना है। इस क्षेत्र में विशेष रूप से युवाओं को नौकरी और उद्यमिता के बड़े अवसर मिलेंगे। उन्होंने एलान किया कि सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 50 स्थलों को चुना है। इन चयनित जगहों को सरकारी मदद दी जाएगी। इसके अलावा बजट पेश करते समय निर्मला सीतारमण ने स्वदेश दर्शन योजना और देखो अपना भारत स्कीम का भी जिक्र किया। स्वदेश दर्शन योजना को सीमा और गांव के पर्यटन के लिए विकसित किए जाने की योजना है।

50 पर्यटन स्थल होंगे विकसित

केंद्रीय बजट 2023-24 में राज्यों की भागीदारी, निजी सार्वजनिक भागीदारी के साथ पर्यटन को बढ़ावा तो युवाओं को रोजगार से रफ्तार मिलेगी। भारत में स्थानीय और विदेशी पर्यटकों के लिए 'असीम आकर्षण' है। इसीलिए एक पैकेज के साथ 50 पर्यटन स्थलों में घूमने का मौका मिलेगा। स्वदेश दर्शन योजना के तहत देश के सीमावर्ती इलाकों और गांवों तक पर्यटकों को जोड़ा जाएगा। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'देखो अपना देश मुहिम' शुरू होगी।

पर्यटन उद्योग को सरकार ने इस बार पिछले बजट की तरह 2400 करोड़ रुपये दिए जाने की घोषणा की है। इनमें से 1644 करोड़ रुपये पर्यटन के आधारभूत ढांचे को संवारने में तथा 1181.30 करोड़ रुपये स्वदेश दर्शन योजना के तहत खर्च किए जाएंगे।

केंद्रीय बजट 2023-24 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा है कि वैश्विक विकास की धीमी गति और चुनौतीपूर्ण वित्तीय परिस्थितियों बावजूद वित्त मंत्री ने विकास को उपयुक्त प्राथमिकता दी है।

उन्होंने कहा, ₹मैं अधिक उत्पादक व्यय के कदम का स्वागत करता हूं। पूंजीगत व्यय के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 33% की वृद्धि की गई है। जीडीपी के हिस्से के रूप में पिछले दो दशकों में यह सबसे अधिक है।

नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब में बदलाव से लोगों की क्रय शक्ति बढ़नी चाहिए। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी और अन्य सहायता, पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करना और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए उठाए गए कदमों से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। बजट में मुफ्त भोजन योजना को एक और वर्ष के लिए बढ़ाकर सरकार ने यह संकेत दिया है कि वह साझा समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है।

स्वदेश दर्शन से होगा विकास

स्वदेश दर्शन के तहत पर्यटन विकास के लिए करोड़ों की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इस योजना के जरिये देश के सभी तीर्थ स्थलों पर परिवहन, आर्थिक स्थिति, रोजगार और भोजन आदि आवश्यक चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत पर्यटन क्षमता वाली जगहों को योजनाबद्ध तरीके और प्राथमिकता के साथ विकसित किया जाएगा। साथ ही उस क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन भी किया जाएगा।

इन पर्यटन स्थलों को बढ़ावा : स्वदेश दर्शन योजना में जिन सर्किटों की फिलहाल पहचान की गई, उनमें बौद्ध तीर्थ स्थल, 5 राज्यों के 12 जगहों पर कृष्ण तीर्थ स्थल, रामायण सर्किट, सूफी परंपरा को कायम रखने वाले पर्यटन स्थल, जैन तीर्थ स्थल, आध्यात्मिक सर्किट हैं, जिनमें सात राज्य शामिल हैं। इन्हें पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जाएगा। इसके अलावा नार्थ ईस्ट सर्किट, ईको सर्किट, ट्राइबल सर्किट, हेरिटेज सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट के संभावित पर्यटन स्थलों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

हरित प्रगति के लिए तय किए गए ये पायदान...

पर्यावरण संरक्षण, परंपरागत खेती, प्रदूषण की रोकथाम, ऊर्जा आत्मनिर्भरता जैसे लक्ष्य हासिल करने में मिलेगी मदद

बजट के सप्तऋषि यानी प्राथमिकता वाले सात क्षेत्रों में हरित प्रगति पांचवें स्थान पर है। इसके जरिये पीएम मोदी के विजन 'लाइफ' यानी 'पर्यावरण अनुरूप जीवन जीने की शैली' पर सरकार ने बताया है वह क्या करने जा रही है। जानिए इस हरित प्रगति के तहत क्या क्या होगा, क्या फायदा मिलेगा।

ऊर्जा भंडारण

यह होगा : 4 हजार मेगावॉट घंटे की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली बनाना। इसके लिए फंडिंग जुटाई जाएगी। पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए भी फ्रेमवर्क बनेगा। ऐसी परियोजनाएं उस वक्त बिजली भंडारण में मदद करती हैं, जब उत्पादन ज्यादा हो, मांग कम।

फायदा : देश की अर्थव्यवस्था को सतत विकास के रास्ते पर लाने में मदद मिलेगी।

ऊर्जा के नए उभरते क्षेत्रों में सिरमौर बनेगा देश

बजट : 19,700 करोड़ रुपये

यह होगा : साल 2030 तक भारत हर साल 50 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने लगेगा।

फायदा : अर्थव्यवस्था को कम कार्बन उत्सर्जित करने वाली अर्थव्यवस्था में बदलना, जीवाश्म ईंधन आयात घटाना और ऊर्जा के नए उभरते क्षेत्रों व तकनीकों के बाजार में देश को सिरमौर बनाना।

ऊर्जा परिवर्तन : प्राथमिकता के आधार पर पूंजीगत निवेश

बजट : 35,000 करोड़ रुपये

यह होगा : आज उपयोग हो रही ऊर्जा के स्वरूप में बदलाव के लिए प्राथमिकता के आधार पर पूंजीगत निवेश।

फायदा : कार्बन उत्सर्जन शून्य करने में मदद और इससे सरकार ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने की ओर आगे बढ़ सकेगी।

ग्रीन क्रेडिट में दे सकेंगे योगदान

यह होगा : पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम बनाया गया था, यह भी पर्यावरण संरक्षण में मदद देगा।

फायदा : हरियाली बढ़ाने में कंपनियां, शहरी निकाय, समुदाय और खुद नागरिक भी योगदान देंगे, जिसकी एवज उन्हें सरकार से मदद मिलेगी।

उम्मीद: लीथीयम बैटरियां सस्ती होने से ई-वाहन के दाम घटेंगे। महंगे पेट्रोल से परेशान जनता ई-वाहनों की ओर आकर्षित होगी।

यह मिला: पर्यटन के लिए किए गए आवंटन से तीर्थस्थलों में परिवहन, आर्थिक स्थिति, रोजगार और होटल के मौके।

आपकी निजता को 100% खत्म करने वाली टेक्नोलॉजी, पढ़ें कैसे आपके घर में ही हो रही है आपकी जासूसी

नई दिल्ली। IoT के बिना आप स्मार्ट होम की कल्पना भी नहीं कर सकते। स्मार्ट फैन, स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट मिक्सर, स्मार्ट लॉक, स्मार्ट एसी, ये सभी IoT के ही गैजेट हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना IoT अधूरा है। 5G ने आईओटी के काम को आसान कर दिया है।

स्मार्ट होम का नाम तो आपने सुना ही होगा। स्मार्ट होम भी किसी स्मार्टफोन से कम नहीं होता। स्मार्ट होम एक ऐसा घर होता है जिसमें हर चीज स्मार्ट होती हैं और आपके इशारे पर काम करती हैं। उदाहरण के तौर पर आपका मन जूस पीने का कर रहा है लेकिन आप उठकर जूस बनाना नहीं चाहते हैं तो स्मार्ट होम की टेक्नोलॉजी आपके लिए यह काम कर सकती है। स्मार्ट होम इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) मॉड्यूल पर काम करती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को बहुत ही आसान भाषा में समझना है तो आप इसे इंटरनेट की चीजें कह सकते हैं। आईओटी मॉड्यूल में सभी तरह के गैजेट और चीजें स्मार्ट होती हैं और इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स पूरी दुनिया के लिए खतरनाक क्यों है?

स्मार्ट होम और इंटरनेट ऑफ थिंग्स

इंटरनेट ऑफ थिंग्स के पैदा होने के बाद ही स्मार्ट होम की शुरुआत हुई है। IoT के बिना आप स्मार्ट होम की कल्पना भी नहीं कर सकते। स्मार्ट फैन, स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट मिक्सर, स्मार्ट लॉक, स्मार्ट एसी, ये सभी IoT के ही गैजेट हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना IoT अधूरा है। 5जी की लॉन्चिंग के दौरान आपने देखा और पढ़ा होगा कि एयरटेल से लेकर जियो और वोडाफोन तक सबने इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सबसे ज्यादा चर्चा की है। इसका बड़ा कारण यह कि एक

सफल IoT मॉड्यूल के लिए एक अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट की जरूरत है।

स्मार्ट एंबुलेंस भी IoT का ही एक हिस्सा है। आपने कुछ हॉलीवुड फिल्मों में वॉयस कमांड से घर के दरवाजे को खुलते हुए देखा होगा। यह भी IoT का ही उदाहरण है। IoT मॉड्यूल का इस्तेमाल ऑटोमेशन में भी बड़े स्तर पर होता है। फिलहाल स्मार्ट होम के अलावा IoT का सबसे ज्यादा इस्तेमाल सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक में हो रहा है, लेकिन यहां IoT से उतना खतरा नहीं है, जितना स्मार्ट होम में IoT से खतरा है, क्योंकि घर एक निजी जगह है। उदाहरण के तौर पर आपके बेडरूम का बल्ब आपके निजी पलों को रिकॉर्ड कर सकता है। इतना समझ लीजिए कि आपने घर को स्मार्ट बना दिया तो आपकी प्राइवेसी खत्म, क्योंकि आपके घर की एक-एक चीजें रिकॉर्ड होंगी और किसी-ना-किसी सर्वर पर स्टोर होंगी।

इंटरनेट ऑफ थिंग्स के खतरे

हाल ही में एशियन लाइट इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि स्मार्ट होम की आड़ में चीन आपको स्मार्ट बल्ब, फ्रिज और कार के जरिए पल-पल देख रहा है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, गोपनीयता और मूल्य और मानव अधिकार के लिए सबसे बड़ा खतरा है। स्मार्ट होम या आईओटी में चीन का नाम ही क्यों सामने आ रहा है।

इसका बड़ा कारण यह है कि अधिकतर स्मार्ट होम या IoT सपोर्ट वाले गैजेट चाइनीज हैं। बाजार में आपको 1,000 रुपये से भी कम में स्मार्ट बल्ब मिल जाएगा और यह बल्ब आपकी जासूसी करने के लिए काफी है। आपकी जासूसी स्मार्ट स्पीकर से भी आराम से हो सकती है। स्मार्ट स्पीकर में वॉयस कंट्रोल होता है। कई बार एलेक्सा को लेकर ही रिपोर्ट सामने आई है यह यूजर्स की बातें सुन रहा है। अमेजन एलेक्सा भी एक स्मार्ट स्पीकर है।

ब्रिटिश राजनयिक चार्ल्स पैट्रोन ने कहा कि सभी देशों को जल्द-से-जल्द चाइनीज IoT मॉड्यूल पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाने चाहिए और सरकारी संपत्तियों और सेवाओं में इनका कहां-कहां इस्तेमाल हुआ है, इसका गहन ऑडिट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक नए चाइनीज IoT मॉड्यूल खरीदने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और 2025 के अंत तक मौजूदा उत्पादों को बदलने के लिए एक समय सीमा जारी की जानी चाहिए।

...तो 100 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी', नीतीश के इस दावे में कितना दम, समझिए समीकरण

एनटीवी न्यूज

नीतीश कुमार ने दावा किया है कि अगर सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाएं तो 2024 में बीजेपी 100 सीट के भीतर ही सिमट जाएगी। उन्होंने विपक्षी दलों को देर न करने और एकजुट होने की अपील की है। लेकिन क्या वाकई अगर विपक्षी दल एकजुट हुए तो बीजेपी दहाई के अंकों में सिमटकर रह जाएगी, आइए समझते हैं।

नई दिल्ली : बिहार की राजधानी पटना। लेफ्ट का कार्यक्रम और मंच पर जेडीयू के शीर्ष नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मंच से वह अपील करते हैं। किसके लिए- कांग्रेस के लिए। अपील ये कि अब देर न करे कांग्रेस। बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टियों को एकजुट कीजिए। तय कीजिए कहां-कहां कौन लड़ेगा। इसके साथ ही नीतीश ने बड़ा दावा किया कि अगर सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हुईं तो अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 100 सीट से भी कम में सिमट जाएगी। जेडीयू नेता के इस दावे में कितना दम है? दावा हवा-हवाई है या वाकई विपक्षी एकजुटता ऐसा करिश्मा कर सकती है? आइए समझने की कोशिश करते हैं।

नीतीश जब कांग्रेस से ये कहते हैं कि देर न करे तो ये सही भी है। आखिर, समय भी तो नहीं है क्योंकि अगले लोकसभा चुनाव में बमुश्किल साल भर ही बचे हैं। लेकिन क्या विपक्षी एकजुटता इतना आसान है? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केसीआर, अरविंद केजरीवाल...सबकी अपनी-अपनी महत्वाकांक्षाएं, सभी प्रधानमंत्री पद के दावेदार, सबके अपने तेवर। इनमें से किसी एक के नेतृत्व में बाकी सभी के साथ आने की संभावना वैसे भी दूर की कौड़ी दिख रही है। लेकिन अगर मान भी लें कि ये सभी किसी एक की अगुआई में एक साथ आ जाएं तो क्या वाकई बीजेपी 2024 में दो अंकों में सिमट जाएगी? वैसे राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं है लेकिन ताजा हालात और पिछड़े आंकड़ों पर नजर डालें तो नीतीश का दावा हवा-हवाई ही दिख रहा है।

विपक्षी एकजुटता बीजेपी की हार की गारंटी नहीं, यूपी सबसे बड़ा उदाहरण

2019 में सियासी लिहाज से सबसे बड़े और अहम सूबे यूपी में बीजेपी के खिलाफ बड़ा गठबंधन हुआ। एक दूसरे की धुर-विरोधी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने साथ मिलकर बीजेपी का मुकाबला किया। लेकिन भारतीय राजनीति में 21वीं सदी का ये सबसे अहम महागठबंधन भी बीजेपी को रोक नहीं पाया। हां, 2014 के मुकाबले उसे 9 सीटें कम आईं लेकिन ये कोई बड़ा नुकसान नहीं था। उलटे बीजेपी का वोटशेयर 2014 के मुकाबले बढ़ भी गया। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में 2014 में बीजेपी ने 71 सीटें हासिल की थी, सहयोगी अपना दल (अनुप्रिया पटेल गुट) के खाते में भी 2 सीटें आई थीं। 2019 में बीजेपी को 62 सीटें और सहयोगी अनुप्रिया पटेल की पार्टी को 2 सीटें मिलीं। अखिलेश यादव और मायावती के साथ आने के बावजूद बीजेपी का वोटशेयर 2014 के 42 फीसदी के मुकाबले बढ़कर 49.98 प्रतिशत हो गया। एनडीए का वोट शेयर 51 प्रतिशत से ज्यादा। दूसरी तरफ, SP+BSP+RLD+अपना दल (सोनेलाल) गठबंधन का कुल वोटशेयर 40 प्रतिशत भी नहीं रहा (39.23%)। एक उदाहरण असम भी है। वहां 2019 में कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की AIUDF साथ मिलकर लड़ी थीं लेकिन बीजेपी की सीटें 2014 के 7 से बढ़कर 9 हो गईं।

2019 में बीजेपी को 16 राज्यों/ UT में मिले 50% वोट

2019 के आंकड़ों पर नजर डालें तो 16 ऐसे राज्य/केंद्रशासित प्रदेश थे जहां बीजेपी का वोटशेयर करीब 50 फीसदी या इससे ज्यादा था। यानी इन राज्यों में बाकी सभी पार्टियों के उम्मीदवारों, निर्दल प्रत्याशियों और NOTA को कुल मिलाकर जितने वोट मिले, उससे ज्यादा अकेले बीजेपी उम्मीदवारों को मिले। उदाहरण के तौर पर-

गुजरात- 62 प्रतिशत (2019 मेंबीजेपी का वोटशेयर)

राजस्थान- 58 प्रतिशत
मध्य प्रदेश- 58 प्रतिशत
दिल्ली - 56 प्रतिशत
हिमाचल प्रदेश- 69 प्रतिशत
उत्तराखंड- 62 प्रतिशत
छत्तीसगढ़- 50 प्रतिशत
हरियाणा- 58 प्रतिशत
अरुणाचल प्रदेश- 58 प्रतिशत
यूपी- 49.9 प्रतिशत
कर्नाटक- 52 प्रतिशत
झारखंड- 52 प्रतिशत
त्रिपुरा- 49 प्रतिशत

200 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को मिले 50+ प्रतिशत वोट

इतना ही नहीं, 543 सीटों वाली लोकसभा में बीजेपी के 200 से ज्यादा मौजूदा सांसद ऐसे हैं जिन्होंने 2019 के चुनाव में करीब 50 प्रतिशत या उससे ज्यादा वोट हासिल किए थे। यानी इन सीटों पर सभी प्रतिद्वंद्वियों और नोटा का वोट भी मिला दें तो बीजेपी उम्मीदवार से कम थे। इनमें गुजरात की सभी 26 सीटें, यूपी की करीब 40 सीटें, एमपी की 25 सीटें, राजस्थान की 23 सीटें, कर्नाटक की 20, बिहार में 14 और हरियाणा की 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी का वोटशेयर 50 प्रतिशत से ज्यादा रहा। इसी तरह दिल्ली में भी सभी 7 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने 50 प्रतिशत से ज्यादा वोट हासिल किए। 8 लोकसभा सीटों- मुंबई नॉर्थ, भिलवाड़ा, नवसारी, सूरत, फरीदाबाद, बडोडरा, कांगड़ा और करनाल में तो बीजेपी का वोटशेयर 70 प्रतिशत से भी ज्यादा था। वैसे बिहार में तब नीतीश बीजेपी के साथ थे और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे। अब दोनों बीजेपी के कट्टर विरोधी हैं।

बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधे मुकाबले वाले राज्यों में गठबंधन बेमानी

गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड...ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसी तीसरी सियासी ताकत का कोई खास वजूद नहीं है। जाहिर है कि अगर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का कोई महामोर्चा बन भी जाए तो इन राज्यों के समीकरण में कुछ खास बदलाव नहीं आएगा। हां, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का थोड़ा मनोबल जरूर बढ़ेगा। इसी तरह तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ खास है भी नहीं। पश्चिम बंगाल में भी किसी तरह के ग्रैंड अलायंस का कोई खास असर होगा, इसकी संभावना कम ही है। सूबे में चुनाव दर चुनाव कांग्रेस और लेफ्ट कमजोर ही होते दिख रहे हैं और मुख्य मुकाबला अब टीएमसी बनाम बीजेपी का ही हो गया है। इसी तरह तेलंगाना में भी मुख्य मुकाबला केसीआर टीआरएस (अब बीआरएस) और बीजेपी के बीच है, वहां कांग्रेस एक तरह से अप्रासंगिक सी हो गई है। कुछ यही हाल दिल्ली का भी है।

सभी विपक्षी दल एक साथ आ जाएं तो इन राज्यों में हो सकता है खेल

वैसे अगर विपक्ष राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक महागठबंधन बनाने में कामयाब हो जाता है तो महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे कुछ ही राज्यों में बीजेपी को नुकसान पहुंचा पाने की स्थिति में होगा। खैर, सियासत में कुछ भी नामुमकिन तो नहीं लेकिन नीतीश का ये दावा कि अगर सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाएं तो बीजेपी दो अंकों में सिमट जाएगी, शायद ही आसानी से किसी सियासी पंडित के गले उतरे।

ब्रीफ न्यूज

राजाओं के घर का वह शख्स जो त्रिपुरा चुनाव में बन सकता है 'किंगमेकर'

नई दिल्ली। त्रिपुरा चुनाव में इन दिनों सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वह टिपरा मोथा पार्टी (टीएमपी) के प्रमुख प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देब बर्मा की। प्रद्योत त्रिपुरा के राजघराने से ताल्लुक रखते हैं और अभी आदिवासियों के लिए अलग से 'ग्रेटर टिपरालैंड' राज्य की मांग कर रहे हैं। इस मांग के साथ टिपरा मोथा ने चुनावी मैदान में भी ताल ठोक दी है। माना जा रहा है कि इस बार चुनाव में टिपरा मोथा के प्रमुख प्रद्योत 'किंगमेकर' साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देब बर्मा के बारे में सबकुछ...

क्यों भाजपा के लिए हो सकती है मुश्किल?
टिपरा मोथा पार्टी ने पिछले साल अप्रैल में हुए त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) के चुनावों में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-आईपीएफटी गठबंधन के साथ सीधे मुकाबले में 'ग्रेटर टिपरालैंड' की मांग पर 28 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। सूबे की 20 विधानसभा सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। राज्य में आदिवासियों की संख्या भी 32 प्रतिशत है। यही कारण है कि भाजपा के सामने बड़ी मुश्किल हो सकती है। चुनाव त्रिकोणीय होने की उम्मीद है। यही कारण है कि इस बार के चुनाव में टिपरा मोथा को किंगमेकर बताया जा रहा है। इसमें कई भाजपा के नेता भी शामिल हो चुके हैं।

कांग्रेस छोड़कर 2019 में पार्टी बनाई
2019 में कांग्रेस से अलग होने के बाद प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देब बर्मा ने 'ग्रेटर टिपरालैंड' की मांग रखते हुए अलग पार्टी बना ली। इसका नाम टिपरा मोथा रखा। प्रद्योत का कहना है कि, 'ग्रेटर टिपरालैंड' मौजूदा त्रिपुरा राज्य से अलग एक राज्य होगा। नई जातीय मातृभूमि मुख्य रूप से उस क्षेत्र के स्वदेशी समुदायों के लिए होगी जो विभाजन के दौरान पूर्वी बंगाल से भारत आए बंगालियों की वजह से अपने ही क्षेत्र में अल्पसंख्यक हो गए थे। 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान बंगाली लोगों की एक बड़ी संख्या ने त्रिपुरा में शरण ली। जनगणना 2011 के अनुसार, बंगाली त्रिपुरा में 24.14 लाख लोगों की मातृभाषा है जो यहां की 36.74 लाख आबादी में से दो-तिहाई है। प्रद्योत अलग राज्य की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अलग राज्य आदिवासियों के अधिकारों और संस्कृति की रक्षा करने में मदद करेगा, जो बंगाली समुदाय के लोगों के आ जाने से अब अल्पसंख्यक हो गए हैं।

कौन हैं प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देब बर्मा
अब प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देब बर्मा के बारे में भी जान लेते हैं। प्रद्योत त्रिपुरा के राजशाही परिवार के प्रमुख हैं। इनका जन्म चार जुलाई 1978 को दिल्ली में हुआ। प्रद्योत त्रिपुरा के 185वें राजा किरीट बिक्रम किशोर देबबर्मा और महारानी बीहूबी कुमारी देवी के बेटे हैं। प्रद्योत की पढ़ाई शिलॉन्ग में हुई है। प्रद्योत के पिता राजा किरीट बिक्रम किशोर देबबर्मा तीन बार लोकसभा के सांसद और मां दो बार विधायक रह चुकी हैं।

उद्धव ठाकरे का 6 सांसद साथ होने का दावा, चार ही आयोग के पास गए, कहां गए 'वो' दो सांसद?

एनटीवी संवाददाता

चुनाव आयोग के फैसले से एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) समर्थकों में जश्न का माहौल है। वहीं इस फैसले से उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के गुट में हड़कंप मच गया है। हालांकि चुनाव आयोग (Election Commission) के इस फैसले का राज्य की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

मुंबई: किसकी शिवसेना? इन मुद्दों पर पिछले सात-आठ महीने से चल रही लड़ाई को आखिरकार एकनाथ शिंदे गुट ने जीत लिया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न देने की घोषणा की। इस फैसले से उद्धव के गुट में हड़कंप मच गया है। इस बीच ठाकरे गुट ने लोकसभा में 6 सांसदों का समर्थन होने का दावा किया है। हालांकि, चुनाव आयोग के दस्तावेजों से ऐसा प्रतीत होता है कि केवल चार सांसद हैं। इससे एक बार फिर चर्चा छिड़ गई है और सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कौन हैं वो दो सांसद?

इलेक्ट्रॉनिक बाजार- स्मार्टफोन जो आपके बजट के अनुकूल हों।

चुनाव आयोग के दस्तावेजों के मुताबिक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में ठाकरे और शिंदे गुट के सांसदों और विधायकों की संख्या की जानकारी जारी की गई। शिंदे गुट के 55 में से 40 विधायक विधानसभा में हैं। ठाकरे गुट के 15 विधायक हैं जबकि विधान परिषद में ठाकरे गुट के 12 में से 12 विधायक हैं और शिंदे के पास शून्य विधायक हैं।

चुनाव आयोग के फैसले के बाद आज शनिवार को उद्धव ठाकरे ने सनरूफ कार से शिवसैनिकों को संबोधित किया।

उद्धव ठाकरे का भाषण सुनने के लिए हजारों की संख्या में शिवसैनिक कलानगर में जमा हुए। इससे पहले शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे ने दशहरा मेले में कार में खड़े होकर शिवसैनिकों को संबोधित किया था। उद्धव ठाकरे ने तपती धूप में सनरूफ कार से शिवसैनिकों को संबोधित किया।

शिवसैनिकों को संबोधित करने से पहले उद्धव ठाकरे ने विधायकों और सांसदों के साथ कई बैठकें भी कीं.

शिवसैनिकों को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा।

क्या दोनों सांसद शिंदे गुट की राह पर?

ठाकरे गुट के राज्यसभा में तीन में से तीन सांसद हैं तो, शिंदे गुट के पास शून्य सांसद हैं। लोकसभा के 19 सांसदों में से शिंदे गुट के 13 सांसद हैं और ठाकरे गुट के केवल चार सांसद हैं। हालांकि, ठाकरे गुट के पास छह विधायक होने का दावा है। दरअसल, चुनाव आयोग को सिर्फ चार सांसदों के हलफनामे मिले हैं। तो क्या ये दोनों सांसद शिंदे गुट की राह पर हैं? या न्यूट्रल रह गए हैं? राजनीतिक गलियारे में यह सवाल उठाया जा रहा है।

आयोग का गणित

पिछले विधानसभा चुनाव में शिवसेना के कुल 55 विधायक चुने गए थे। एकनाथ शिंदे गुट के 40 विधायक हैं और उन्हें मिले वोट 36,57,327 हैं। उद्धव गुट के 15 विधायक हैं और उन्हें मिले वोट 11,25,113 हैं।

तमंचे को लेकर हुई छीना-झपटी, दारोगा के हाथ में लगी गोली, महाशिवरात्रि पर आरोपी कर रहा था फायरिंग

अमरोहा में एक दारोगा को उस समय गोली लग गई जब महाशिवरात्रि में शिवभक्तों को लेकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली आई। मंदिर के पास आने के बाद ट्रैक्टर चलाने वाले शख्स ने तमंचे से फायरिंग कर दी। यह सुनकर मंदिर की सुरक्षा में मौजूद दारोगा ने उसका तमंचा छीनने की कोशिश की।

अमरोहा: अमरोहा जिले में एक युवक से तमंचा छीनने के दौरान दारोगा (Amroha Police Cop Shot) को गोली लग गई। आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। दारोगा के हाथ में गोली लगी है, फिलहाल, उनका इलाज चल रहा है। महाशिवरात्रि पर शिवभक्त एक ट्रैक्टर में सवार थे। इसी दौरान ट्रैक्टर सवार एक युवक ने मुंढ़ा खेड़ा गांव में तमंचे से फायरिंग कर दी थी। सूचना पर पहुंचे दरोगा की आरोपी से तमंचे को लेकर छीना-झपटी हो गई। खींचतान में तमंचे से गोली चल गई। गोली दरोगा के हाथ में लगी। थाने की पुलिस ने पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास दो कारतूस के खोखे, तमंचा और ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर लिया है। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। घटना शनिवार की महाशिवरात्रि पर्व के दौरान की अमरोहा जिले के नौगांवा सादात थाना क्षेत्र के मुंडा खेड़ा गांव की है। दरअसल, गांव के शिव मंदिर में जलाभिषेक किया जा रहा था। गांव रतनपुर खुर्द के ग्रामीण भी हरिद्वार से कांवड़ में गंगाजल लेकर आए थे। शनिवार दोपहर करीब साढ़े ग्यारह बजे वे ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर रतनपुर खुर्द के शिव मंदिर जा रहे थे। गांव का चमन सिंह ट्रैक्टर चला रहा था। डीजे भी लगा हुआ था। पुलिस के मुताबिक मुंडा खेड़ा गांव में पहुंचने पर चमन सिंह ने तमंचे से फायरिंग कर दी। सूचना पर मंदिर में सुरक्षा में तैनात दारोगा महेंद्र शर्मा पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचे। चमन सिंह की ट्रैक्टर से उतारकर तलाशी ली तमंचा बरामद कर लिया। आरोपी ने दारोगा से तमंचा छीनने की कोशिश की। छीना-झपटी में तमंचे से चली गोली दरोगा महेंद्र शर्मा के हाथ में लगी। उसके बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। दारोगा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी चमन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मौके पर इस दौरान भीड़ एकत्र हो गई। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। एसपी अमरोहा आदित्य लांग्हे के मुताबिक मुंडा खेड़ा गांव में फायरिंग की सूचना पर दारोगा टीम के साथ पहुंचे थे। एक आरोपी से तमंचा बरामद हुआ था। तमंचे से चली गोली से दारोगा के हाथ में लगी है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

बीजेपी के अंदाज में ही महागठबंधन की जवाब देने की तैयारी, हिंदुत्व के बदले एमवाई समीकरण का अस्त्र

एनटीवी संवाददाता

बिहार की राजनीति में 25 फरवरी का दिन अहम साबित होने जा रहा है। इस दिन न सिर्फ अमित शाह बिहार आ रहे हैं बल्कि महागठबंधन के सभी दल भी एक साथ बीजेपी को चुनौती देने के लिए उतरेंगे। क्या है पूर्णिया में महागठबंधन की रैली और अमित शाह के कार्यक्रमों के मायने, पढ़िए यहां...

पटना: आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदुत्व की गोलबंदी का मकसद लिए सीमांचल से चुनावी शंखनाद 23 और 24 सितंबर को किया था। महागठबंधन उसी अंदाज में और उसी तेवर से भाजपा को जवाब देने की तैयारी कर रही है। इलाका भी सीमांचल ही है। महागठबंधन ने भाजपा को उसी की रणनीति से परास्त करने केलिए 25 फरवरी को पूर्णियां में रैली का आह्वान किया है। दरअसल राजद इस रैली को पहले करना चाहती थी मगर नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को ले कर तारीख को 25 फरवरी तक खिसकाया गया। यह एक संयोग है कि इसी दिन भाजपा के कद्दावर नेता अमित शाह भी बिहार आने वाले हैं। पर उनके आने की वजह है स्वामी सहजानंद की जयंती समारोह जो भाजपा पटना के बापू सभागार में ममाने जा राही है।

क्या है महागठबंधन की रणनीति?

जातीय चेतना के आधार पर महागठबंधन की राजनीति की बात करें तो इधर हुए उपचुनाव में राजद के एमवाई समीकरण की धार कुंद हुई है। इसकी दो वजहे हैं, एक तो नरेंद्र मोदी का नारा सबका साथ सबका विकास ने इस समीकरण को कमजोर किया। दूसरा देश की सुरक्षा और संस्कृति की सुरक्षा के नाम पर हुई गोलबंदी ने भी एमवाई समीकरण को नुकसान पहुंचाया। तीसरी वजह यह है कि सीमांचल को चुने जाने के पीछे एक मकसद यह भी है कि ओवैसी फैक्टर की काट निकाली जा सके। पिछले चुनाव और उपचुनावों में ओवैसी ने महागठबंधन को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है।

लालू-नीतीश की जोड़ी से अतिपिछड़ा पिछड़ा समीकरण दरका

पिछले दिनों हुए उपचुनाव में ऐसा कुढ़नी, मोकामा, गोपालगंज में भी देखने को मिला कि अतिपिछड़ा और पिछड़ा वोट दरक गया है। इसके पीछे का कारण यह बताया जा रहा है कि लगातार 15 साल नीतीश कुमार माइनस यादव पिछड़ों की राजनीति करते रहे हैं। यह राजनीति लगभग डेढ़ दशक में इतनी गहरी हो गई है कि केवल नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के एक साथ होने से वह दूरी कम नहीं होगी। इसलिए भी एक मंच पर दिखने को महागठबंधन ने यह रणनीति बनाई है। महागठबंधन के भीतरखाने से यह खबर आ रही है कि इस तरह की रैली वर्ष 2024 के पहले सभी जिलों में की जाएगी ताकि एमवाई और पिछड़ों-अतिपिछड़ों की राजनीति को पूरे तौर पर महागठबंधन के प्लेटफार्म पर उतारा जा सके।

बिहार यात्रा और रैलियों का राज्य

बिहार में सियासी खेला चरम पर है। पार्टियां अपनी नीतियों को रैली और यात्रा के जरिए बताने निकल पड़ी है। लगभग तमाम दल यात्राओं के जरिए जनता की नब्ज टटोल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का समापन हो गया है। हम प्रमुख जीतनराम मांझी भी गरीब संपर्क यात्रा पर निकले हैं। कांग्रेस भी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के जरिये जनता को साथ जोड़ने की कवायद में है। माले भी महाधिवेशन के जरिये शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश में है और इन सब के बीच महागठबंधन के ये तमाम साथी एक मंच पर साथ आने वाले हैं। अब तक अलग-अलग यात्रा पर निकले महागठबंधन के ये तमाम घटक दल अब 25 फरवरी को एक मंच पर आकर भाजपा को चुनौती देन के मूड में आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पहली बार नीतीश कुमार, जीतनराम मांझी, तेजस्वी यादव और माले के तमाम नेता पूर्णिया में एक मंच पर दिखने वाले हैं। 25 फरवरी को होने वाली इस रैली पर विशेष तौर पर भाजपा की नजर है। इसी दिन गृहमंत्री अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं।